RNI No : CHHHIN/2015/64212 | वर्ष – 02 | अंक – 11 | राजनांदगांव | पृष्ठ 32 आवरण सहित

15 मई – 14 जून, 2017

मूल्य 20 रुपए

# नेशन अलर्ट

मासिक पत्रिका

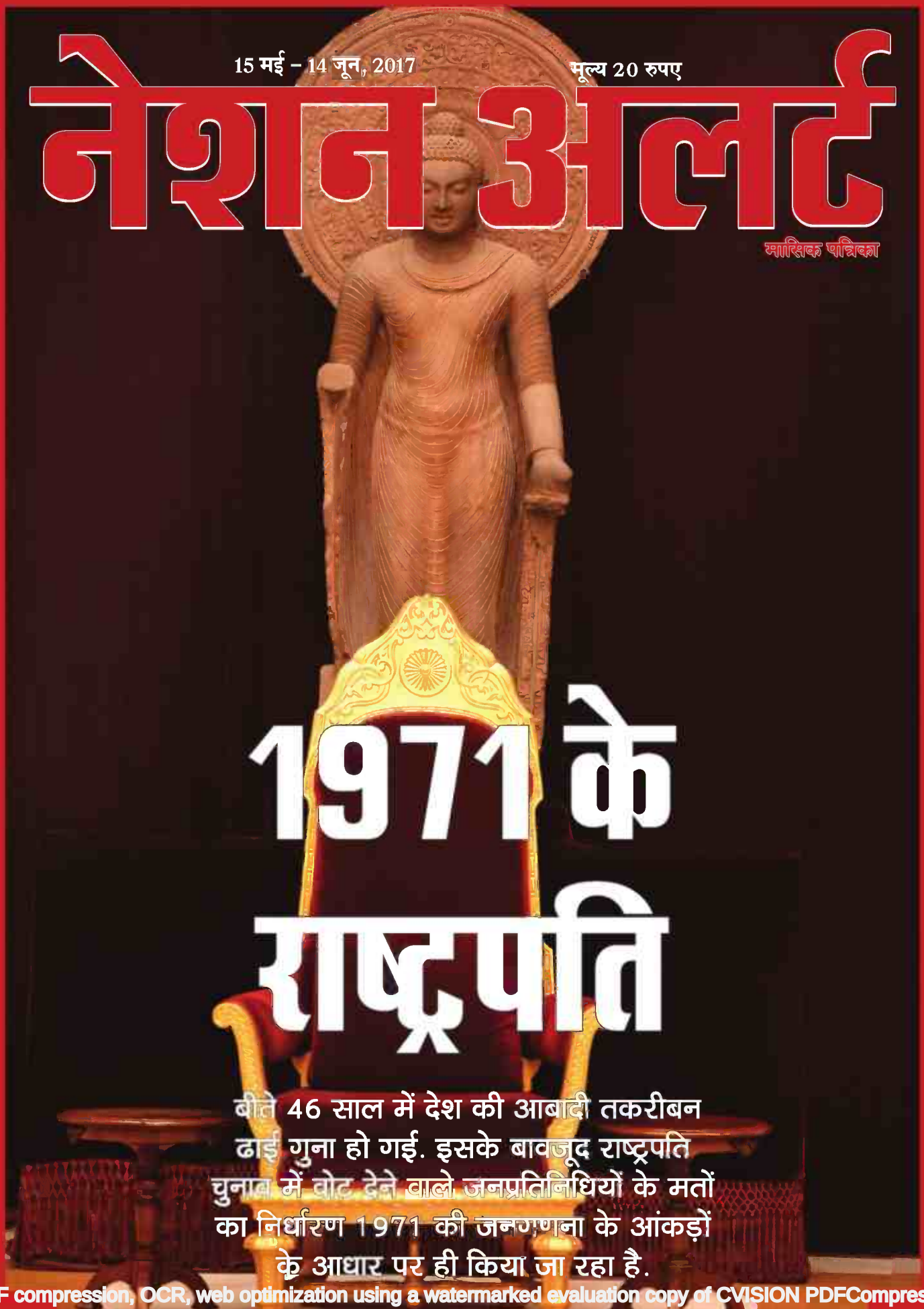

# 1971 के राष्ट्रपति

बीते 46 साल में देश की आबादी तकरीबन ढाई गुना हो गई. इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले जनप्रतिनिधियों के मतों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा रहा है.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# रमजान मुबारक

शाहिद भाई

रॉयल कंस्ट्रक्शन,

राजनांदगांव

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

श्री पितृ कृपा से...
मासिक पत्रिका
# नेशन अलर्ट
■ वर्ष - 02 ■ अंक - 11 ■ मई 2017 ■ पृष्ठ 32 ■ मूल्य 20 रुपए

संपादक: आशीष शर्मा
परामर्शदाता: जरनैल सिंह भाटिया, अतुल श्रीवास्तव, आशीष दुबे, सैय्यद शोएब अली
कार्यकारी संपादक: श्रीमती नीता शर्मा
सहायक संपादक: विक्रम बाजपेयी
संपादकीय सलाहकार: जयदीप शर्मा
ऑपरेशंस संपादक: अशोक शर्मा
फीचर संपादक: आरती शर्मा, रजनी शर्मा
प्रमुख संवाददाता: श्याम शर्मा, सूरज शर्मा
व्यापारिक प्रतिनिधि : राकेश जैन, तुषार साहू
धर्म-आध्यात्म प्रतिनिधि : त्रिलोक सोनी
डिजाइन: वी उपमन्यु
फोटो: जितेंद्र जैन, मनोज देवांगन
संपादकीय एक्जीक्यूटिव: श्रीमती दीनिता शर्मा
**विज्ञापन:**
सीनियर जनरल मैनेजर: एडी वैष्णव
जनरल मैनेजर: पंकज महेश्वरी
रीजनल मैनेजर: लोकेश सवाणी
सीनियर मैनेजर: हर्षद कुमार
**सर्कुलेशन:**
स्टेट हेड: पंकज शर्मा
असिस्टेंट जनरल मैनेजर: राजेश शर्मा
**प्रोडक्शन:**
सीनियर मैनेजर: प्रेमचंद शर्मा
मैनेजर: तेजस कुमार
**स्टेट ब्यूरो**
छत्तीसगढ़ : धीरेन्द्र शर्मा
दिल्ली एनसीआर : गौरव तिवारी
मध्यप्रदेश : अनिल शर्मा
महाराष्ट्र : अरुण शर्मा
उड़ीसा : आर शर्मा
आंध्रप्रदेश : राकेश शर्मा
तमिलनाडु : नीरज शर्मा
**विधि सलाहकार :**
रुपेश दुबे, विमल हाजरा

सभी अवैतनिक*

**कार्यालय :**
'नेशन अलर्ट' प्लॉट नंबर 29, विकास नगर, लखोली, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
097706-56789, 097524-11311, 098271-15077
E-mail : nationalertcg@gmail.com

**आंचलिक कार्यालय :**
धीरेन्द्र शर्मा, सत्तीमाता मंदिर के पास, सत्ती बाजार,रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक आशीष शर्मा द्वारा श्री बाबा रामदेव प्रिंटर्स, मकान क्रं. 74, वार्ड नं. 37 रानीसागर पूर्व भाग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मकान क्रं. 74, वार्ड नं. 37 रानीसागर पूर्व भाग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से प्रकाशित – संपादक आशीष शर्मा।

■ सभी विवादों का निपटारा राजनांदगांव की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

## इस माह | आवरण कथा

# 1971 के राष्ट्रपति

बीते 46 साल में देश की आबादी तकरीबन ढाई गुना हो गई. इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले जनप्रतिनिधियों के मतों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा रहा है.

**07** ओड़िसा

### चुनावी आगाज हो चुका है...

पिछले कुछ समय के दौरान भाजपा ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे लगता है कि 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनावों को लेकर वह अभी से ही पूरी ताकत झोंक रही है.

**13** ऑटो

### टाटा का हर नया कदम एक गलती बन गया

वाहन कंपनियां आमतौर पर लोगों के ध्यान में तब आती हैं जब वे किसी सेगमेंट में नया वाहन लॉन्च करती हैं. लेकिन भारत के कार बाजार में एक ऐसी कंपनी भी है जिसे गाड़ियों से ज्यादा सेगमेंट लॉन्च करने के लिए जाना जाता है.

**27** क्रिकेट

### कटघरे में जेंटलमैन

हाल ही में सार्वजनिक हुए बीसीसीआई के नये संविधान के दो नियम राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को कठघरे में खड़ा करते हैं...

**20** बॉलीवुड

### ये है सबसे 'विवादास्पद फिल्म'!

आज सोशल मीडिया से लेकर किसी भी राजनैतिक पार्टी को ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कलाकारों ने फिर से यहां काम करना शुरू कर दिया है. अब उनपर कोई रोक टोक नहीं है.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संपादकीय

आशीष शर्मा

# बेचारा बनकर भूपेश फायदा न ले जाएं...

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल इन दिनों चर्चा का विषय हैं। दरअसल, उनके खिलाफ एक मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्लू) में दर्ज किया गया है। मामला तब का है जब भूपेश दुर्ग जिले की राजनीति में सक्रिय थे और साडा से जुड़े हुए थे।

मामले की शुरूआत तब हुई जब भूपेश के एक पुराने साथी विधान मिश्रा ने उन पर आरोप लगाया। तब भूपेश ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया था कि विधान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे के सुप्रीमो अजीत जोगी के इशारे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तब जोगी की मित्रता मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी गिनाई थी।

आरोप प्रत्यारोप के बीच मामले में तब नया मोड़ आया जब राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने यह कहते हुए जानकारी दी कि कहीं न कहीं भूपेश व उनका परिवार इस मामले में दोषी है। अब जाकर जब भूपेश की पत्नी व उनकी बुजुर्ग माताश्री को ईओडब्लू ने आरोपी बना दिया है तो इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।

आरोप-प्रत्यारोप के बीच मामले में हर कोई अपने-अपने नजरिए से इसकी व्याख्या कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि विधान मिश्रा ने सारा मामला रविंद्र चौबे के कहने पर उजागर किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्र और विधान हालही में समधी बने हैं। रविंद्र राज्य की राजनीति में भूपेश की जगह लेना चाहते हैं। कुछ लोग इसे टीएस सिंहदेव से जोड़कर देखते हैं।

कुछ इसे भाजपा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे की जुगलबंदी से जोड़कर लोगों के सामने रखते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसे ईओडब्लू प्रमुख मुकेश गुप्ता से जोड़क र देखते हैं। उल्लेखनीय है कि गुप्ता कहीं न कहीं भूपेश के निशाने पर रहे हैं। उन्होंने ईओडब्लू की कार्रवाई को लेकर कई दर्जन सवाल दागे हैं। इधर, गुप्ता को जैसे ही फाईल मिली वैसे ही उन्होंने मामला दर्ज कर लिया बताया जाता है। जबकि सूत्र तो यह तक कहते हैं कि जब गुप्ता के हाथ इंटेलिजेंस विंग हुआ करती थी तब से ही फाईल उनके पास थी और उन्हें सहीं समय का इंतजार था।

राजनीति के जानकार लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अजीत जोगी जैसा धुरंधर खिलाड़ी स्वयं कहता है कि भूपेश कहीं बेचारा बनकर मामले में फायदा न ले जाएं। जोगी के अपने तर्क भी हैं। जोगी कहते हैं कि पत्नी व मां को भले ही शपथ पत्र के आधार पर आरोपी बनाया गया है लेकिन भूपेश

★★★

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# राजनीतिक स्वार्थ की बलि चढ़ाने सत्तारुढ़ पार्टी तैयार है ?

**दिवाकर मुक्तिबोध**

बस्तर में नक्सलियों से अब आर-पार की लड़ाई है, जब तक उनका सफाया नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे-28 अप्रैल को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यही कहा. उन्होंने यह भी कहा कि अब नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी. बस्तर में नक्सली हिंसा पर मुख्यमंत्री की चिंता, बेचैनी और नाराजगी स्वाभाविक है.

वर्ष 2003 से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य की इस भीषणतम समस्या जो राष्ट्रीय भी है, पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है. और तो और मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 2013 से जारी उनके तीसरे कार्यकाल में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं तथा हिंसा का ग्राफ और उपर चढ़ा है. राज्य के नक्सल इतिहास में सर्वाधिक स्तब्धकारी घटना अप्रैल 2010 में बस्तर के ताड़मेटला में घटित नक्सल हमला था जिसमें केन्द्रीय सुरक्षा बल के 75 जवान मारे गए थे. तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी. इस नरसंहार से पूरे देश में शोक और गुस्से की जबरदस्त अभिव्यक्ति हुई.

सरकार ने नक्सलियों से निपटने कमर कसी, व्यूहरचनाएं बनाई गई, बड़ी-बड़ी बातें की गई, छत्तीसगढ़ में संयुक्त अभियान चलाया गया और देश की जनता को यह भरोसा देने की कोशिश की गई कि घुआंधार विकास और बंदूक के जरिए नक्सलियों को खत्म किया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों में अमन चैन लौटेगा, शांति कायम होगी, हिंसा थमेगी. लेकिन 6 वर्ष बीत गए इस भरोसे का क्या हुआ? कम से कम छत्तीसगढ़ में यह तो टूटा ही. बस्तर में विकास का यह आलम है कि धूर नक्सली क्षेत्र दोरनापाल से जगरगुंड़ा तक 56 कि.मी. सड़क 40 वर्षों से नहीं बन पाई है.

राज्य सरकार के लिए बस्तर में सड़कों और गांवों तक पहुंच मार्गों का निर्माण किस कदर महत्वपूर्ण और जोखिम भरा है, यह हाल ही में 24 अप्रैल को सुकमा जिले के बुकार्पाल में घटित घटना से जाहिर है. सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ के 25 जवान आतंकी हमले के शिकार हुए और जान गंवा बैठे. दो माह के भीतर सीआरपीएफ पर यह दूसरा बड़ा हमला था, पहले से बड़ा. पिछले महीने 11 मार्च को इसी जिले के दुकार्पाल में सीआरपीएफ कैम्प के निकट नक्सलियों ने हमला बोला था जिसमें 11 जवान शहीद हो गए. दो माह के भीतर 36 जवानों की शहादत से एक बार फिर वैसा ही माहौल बना है जैसा कि ताड़मेटला कांड के बाद बना था. यानी मातम भरी स्तब्धता, विशेष कुछ न कर पाने की विवशता और नक्सलियों के प्रति नफरत और गुस्सा.

नक्सलियों को नेस्तनाबूत करने का सरकार का संकल्प, आर-पार की लड़ाई का संकल्प, विकास की बयार बहाने का संकल्प व नक्सलियों से अब किसी भी तरह की वार्ता न करने का संकल्प जो अभी तक कभी हुई ही नहीं. हालांकि इस बार एक विशिष्टता यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नक्सलियों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में सीधा दखल होगा तथा नक्सली कमांडरों को बिलों से बाहर निकालने पूरी ताकत झोंकी जाएगी. राज्य सरकार के सहयोग से

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of PDFCompressor

आपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. इसे केन्द्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही बस्तर में अभियान की शुरूआत हो जाएगी.

सवाल है क्या अब वास्तव में आर-पार की लड़ाई होगी, क्या वांछित नक्सली नेता मारे जाएंगे या गिरफ्तार होंगे और क्या बस्तर के सैकड़ों गांवों को नक्सल मुक्त किया जा सकेगा? बस्तर की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए क्या यह एक झटके में संभव है? क्या आदिवासियों को नक्सली आतंक से छुटकारा मिल सकेगा? क्या उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी. और क्या सरकार के प्रति उनका विश्वास लौटेगा? नजरिया बदलेगा!

इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता. आखिरकार देश में नक्सल हिंसा की लहर पिछले लगभग पांच दशक से चली आ रही है. पिछले दो दशक की बात करें तो नक्सली घटनाओं में अब तक १४ हजार से अधिक लोगों की जाने गई जिसमें लगभग ८ हजार नागरिक हैं. इन आंकड़ों से समस्या की गहराई को समझा जा सकता है. लिहाजा बुकार्पाल घटना के बाद केंद्र व राज्य सरकार का आर-पार की लड़ाई का संकल्प यानी बस्तर को नक्सलमुक्त करने का संकल्प कामयाब हो पाएगा, कहना मुश्किल है. दरअसल जन हिंसा की लगभग प्रत्येक बड़ी घटना के बाद सरकार ऐसे ही संकल्प दोहराते रही है लिहाजा यह खंडित विश्वसनीयता के दायरे में है. जाहिर है इस पर भरोसा कम होता है.

यह आश्चर्य की बात है कि सरकार सिर्फ बंदूक पर क्यों विश्वास करती है. क्या हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा है और क्या इससे समस्या का समाधान, उसका अंत संभव है? अगर ऐसा होता तो जम्मू-कश्मीर भी यूं न जलता रहता हालांकि वहां की परिस्थितियां अलग हैं और वे राजनीतिक भी हैं. बस्तर भी जल रहा है तो इस वजह से क्योंकि सरकार आदिवासियों की विश्वासपात्र नहीं बन सकी है, उन्हें पूंजीवादी शोषण से मुक्त नहीं कर सकी है, अपने शोषक अफसरों व पुलिस की प्रताड?ा से बचा नहीं सकी है और उन्हें जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के सुनियोजित अभियान को भी रोक नहीं सकी है बल्कि इसमें उसकी सहभागिता रही है.

ऐसी स्थिति में बस्तर का आदिवासी अलग-थलग पड़ गया है इसलिए नक्सली आतंक को झेलना और नक्सलियों को शरण देना उसकी मजबूरी है. सरकार उनकी इस मजबूरी को समझती है लेकिन इस दिशा में क्या कभी कोई सार्थक पहल हुई है? क्या कभी उनका दिल जीतने ईमानदार कोशिश हुई है? अगर हुई होती तो ऐसी नौबत न आती.

अब केन्द्र व छत्तीसगढ़ सरकार निर्णायक लड़ाई चाहती है. किंतु इसके पहले कि सशस्त्र अभियान शुरू हो, क्या उन आदिवासियों के बारे में सोचा गया है जो सरकारी प्रतिहिंसा के शिकार हो सकते हैं. बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर व दंतेवाड़ा जिले में गांवों के आसपास नक्सलियों के शिविरों पर हमला करने के पूर्व क्या इस बात की गारंटी होगी कि गांव महफूज रहेंगे? कोई ग्रामीण नहीं मारा जाएगा?

यह नहीं भूलना चाहिए कि नक्सली पुलिस से मुठभेड़ की स्थिति में आदिवासी युवकों, युवतियों व बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं यानी ऐसी मुठभेड़ हुई तो निहत्थे आदिवासी ही पहले मारे जाएंगे. नक्सली कमांडरों को मार गिराना तो खैर जायज होगा लेकिन बरगलाए गए, भटके हुए विवशता में बंदूक थामने वाले, आदिवासी युवा व युवतियों को गोलियों का निशाना बनाना न्यायोचित होगा? नहीं तो फिर बेहतर उपाय यही है कि बातचीत के दरवाजे बंद न किए जाए. समस्या इसलिए विकराल होती चली जा रही है क्योंकि राज्य अथवा केन्द्र सरकार के स्तर पर सार्थक पहल नहीं हुई. केवल बातें होती रही.

सवाल है क्यों नहीं माओवाद समर्थक जाने-माने साम्यवादी नेताओं, बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाकर उनके माध्यम से, उनकी मध्यस्थता में नक्सल नेताओं को वार्ता के लिए राजी करने की कोशिश की गई. क्यों नहीं ऐसा अभियान चलाया गया. श्री श्री रविशंकर जैसे आध्यात्मिक गुरू राज्य सरकार से बीजापुर में जमीन तो मांग सकते हैं पर स्वयं नक्सली इलाकों में जाकर उन्हें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने का साहस नहीं दिखा सकते, उनका मन नहीं जीत सकते. और भी महात्मा संत हैं, धर्मगुरु हैं जो नक्सल मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं, मानवाधिकार की हिमायत करने वाले प्रखर बुद्धिजीवी हैं, समाजशास्त्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं.

क्यों नहीं जगदलपुर को राज्य की उपराजधानी बनाने सरकार पर दबाव बनाया गया? क्या ही अच्छा होता यदि वे नक्सल इलाकों में डेरा-डालते, उनसे वार्ता के लिए आगे आने का आग्रह करते. सरकार उन्हें भरोसा देती कि वह बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगी. उनके प्रति सहानुभूति का रुख अपनाएगी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी और उन्हें सुरक्षित जीवन जीने का मौका देगी बशर्ते वे हथियार डाल दें तथा हिंसा से तौबा करे.

दरअसल यह बंदूक का नहीं अविश्वास पर विश्वास की जीत का अभियान होना चाहिए. सचमुच यदि ऐसी कोई पहल होती तो नक्सल समस्या से निजात की उम्मीद बंधती. इसी संदर्भ में यहां एक सवाल है- नक्सल मोर्चे पर केन्द्र व राज्य सरकार की चाक-चौबंद व्यवस्था व प्रत्येक पहलू पर विचार के बाद बनाई गई कार्ययोजना यदि असफल होती है, यदि इस बार आर-पार की लड़ाई में नक्सलियों से पार नहीं पाया जा सका तो क्या सरकार बस्तर में पांचवीं व छठवीं अनुसूची लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी? बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक ई.एन. राममोहन, डॉ. ब्रम्हदेव शर्मा सरीखे अनेक विद्वानों व आदिवासी नेताओं ने समय-समय पर राय व्यक्त की है कि बस्तर में आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए जो संविधान सम्मत है.

संविधान में आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासी विकास परिषद के जरिए राज्यपाल को शासन करने का अधिकार है. राममोहन का कहना है कि आज तक कभी भी किसी भी राज्यपाल ने संविधान के इस हक का पालन नहीं किया. यदि ऐसा किया गया होता, आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से सत्ता चलायी जाती तो आज स्थितियां दूसरी होती. जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक होता. और नक्सलवाद को पनपने का मौका नहीं मिलता.

यकीनन बस्तर में शांति लौटाने का यह बहुत सीधा व सरल तरीका है पर राज्यपाल कोई जोखिम उठाने इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी नियुक्तियां राजनीतिक हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान से किसी तरह का टकराव नहीं चाहती. जाहिर है यदि आदिवासी विकास परिषदों को सत्ता सौंपी गई और राज्यपाल का शासन लागू हुआ तो राज्य में सत्ता के दो केंद्र बनेंगे. कोई राजनीतिक पार्टी अपने हितों की रक्षा के लिए इस फामूर्ले को मंजूर नहीं कर सकती, भले ही मासूमों, निरपराधों का खून निरंतर क्यों न बहता रहे. लेकिन राज्य के दीर्घकालीन हितों को देखते हुए क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस बारे में विचार करेगी? बस्तर में शांति लौटाने के लिए क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ की बलि चढ़ाने सत्तारुढ़ पार्टी तैयार है? शायद नहीं. यकीनन नहीं. लेकिन एक समाधान तो यह है ही जिस पर विचार किया जाना चाहिए.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# ओड़िशा में चुनावी आगाज हो चुका है!

पिछले कुछ समय के दौरान भाजपा ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे लगता है कि 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनावों को लेकर वह अभी से ही पूरी ताकत झोंक रही है

**हिमांशु शेखर**

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी गुजरात और ओडिशा में सबसे अधिक जोर लगाते दिख रही है. गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है. इस नाते यहां भाजपा की सक्रियता बेहद स्वाभाविक लगती है. लेकिन ओडिशा में विधानसभा चुनावों में अभी दो साल की देर है, इसलिए यहां अभी से पार्टी का इतना सक्रिय होना काफी हद तक चौंकाता है.

पिछले कुछ समय के दौरान भाजपा ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे लगता है कि 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनावों को लेकर वह अभी से ही पूरी ताकत झोंक रही है. हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक ओडिशा में आयोजित की गई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता और मुख्यमंत्री पहुंचे. कार्यकारिणी आयोजित करने के लिए भाजपा द्वारा ओडिशा को चुने जाने को भी राज्य के अगले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा ओडिशा में पैर जमाने की कोशिश कर रही है.

कार्यकारिणी के लिए ओडिशा गए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी दौरे में पैका विद्रोह के नायकों के परिजनों को सम्मानित किया. माना जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में हुए पैका विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर इसे याद करना और इससे जुड़े लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित कराके भाजपा ओडिशा के आम लोगों से एक जुड़ाव विकसित करने की कोशिश कर रही है. साथ ही यह भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भाजपा ऐसे कार्यक्रमों के जरिए कुछ स्थानीय नायकों को उभारने की कोशिश कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने पैका विद्रोह से जुड़े कार्यक्रम में उस विद्रोह के नायक मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, कृष्ण चंद्र गजपति और गंगाधर मेहर की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया. इन नायकों को याद करके कहीं न कहीं भाजपा यह संदेश देती दिख रही है कि स्थानीय नायकों के प्रति पार्टी कितना सम्मान रखती है.

अपने इसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर भी गए. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि 17 सालों से राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद अब तक वे उड़िया संस्कृति के साथ संबंध स्थापित करते नहीं दिखते. वे उड़िया भाषा भी नहीं बोल पाते. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे में मोदी का मंदिर जाना और वहां महामृत्युजय मंत्र जाप में शामिल होना नवीन पटनायक की इसी कमजोरी का फायदा उठाने की राजनीतिक कोशिश है.

ए९सी कोशिश सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर ही नहीं दिख रही है बल्कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी कुछ इसी कवायद में जुटे दिख रहे हैं. पार्टी कार्यकारिणी के लिए अमित शाह एक दिन पहले ही ओडिशा पहुंच गए थे. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उड़िया नववर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. ओडिशा में नव वर्ष पर पन्ना पीने का रिवाज है. अमित शाह भी इस मौके पर पन्ना पीते दिखे. इस मौके पर आयोजित संकीर्तन में भी शाह शामिल हुए.

कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ओडिशा के लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वहां की संस्कृति का सम्मान नवीन पटनायक के मुकाबले अधिक करता है. नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के कुछ नेताओं ने बीते दिनों यह आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है. बीजू जनता दल के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेताओं को पैसे का प्रस्ताव देकर भाजपा अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है. ओडिशा के ढेनकनाल से बीजद सांसद तथागत सत्पथी ने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा अन्नाद्रमुक की तरह उनकी पार्टी तोड़कर राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहती है.

कुछ समय पहले बीजद सांसद बैजंत जय पांडा के बारे में इस तरह की खबरें आई थीं कि उनकी भाजपा से नजदीकी बढ़ रही है और उनकी मदद से भाजपा बीजद को तोड़ना चाहती है. हालांकि, पांडा ने इन आरोपों को खारिज किया है. केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर काम कर रहे धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में भाजपा के पूरे अभियान की अगुवाई करते दिख रहे हैं.

चर्चा है कि वे अपने मंत्रालय की कुछ परियोजनाएं भी ओडिशा में अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही ले जा रहे हैं. उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा वहां जीतती है तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं. हाल ही में ओडिशा में हुए पंचायत चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से अच्छा रहा है. इसके बाद से पार्टी को लग रहा है कि वहां वह अगले विधानसभा चुनावों में बाजी मार सकती है. अब तक दूसरे राज्यों में पार्टी रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी यह माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के आला नेताओं को यह भरोसा दिलाया है कि उनके गृह राज्य में पार्टी सत्ता में आ सकती है.

ओडिशा में सरकार बनाने के लिए 147 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 74 विधायक चाहिए होंगे. यही वजह थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए ओडिशा पहुंचे अमित शाह को धर्मेंद्र प्रधान ने 74 फूलों वाली माला पहनाई.

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of PDFCompressor

# लालू की कमजोरी ही नीतीश की ताकत है

**चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ फिर से सुनवाई के आदेश और शहाबुद्दीन के साथ बातचीत का ऑडियो आने के बाद नीतीश कुमार सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करते दिख रहे हैं...**

**हेमंत कुमार पाण्डेय**

बीते कुछ समय के दौरान बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश व अन्य धाराओं के तहत मामलों की अलग-अलग सुनवाई करने का आदेश दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शीर्ष अदालत में इसके लिए अपील की थी. इसके अलावा बीते रविवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें राजद सुप्रीमो सिवान जेल में बंद पार्टी के पूर्व सासंद मोहम्मद शहाबुद्दीन से बातचीत करते दिखे थे. इससे पहले भाजपा ने लालू यादव के परिवार पर 90 लाख रुपये के मिट्टी घोटाले से लेकर पटना और दिल्ली में करोड़ों रुपये की कई बेनामी संपत्तियां रखने के आरोप लगाए हैं. लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे- तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और दो बेटियां इन आरोपों की चपेट में हैं. इससे भाजपा के खिलाफ देशभर में आंदोलन की बात करने वाले राजद सुप्रीमो अब अपने परिवार के साथ खुद पर लग रहे आरोपों की वजह से मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं.

वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार के सदस्यों पर लग रहे आरोपों की सीबीआई जांच कराने के साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को सरकार से बर्खास्त करने की मांग की है. दोनों पर चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथपत्र में गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट में दोनों मंत्रियों के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है. इन आरोपों के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने सुशील कुमार मोदी को भ्रष्ट बताया है.

## नीतीश की चुप्पी

रवाज्य में भाजपा और राजद के नेता जहां एक-दूसरे पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर अपनी चिर-परिचित चुप्पी साधे हुए हैं. पटना में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा इस मामले पर लगातार सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, ज्यादा बोलने पर गला खराब हो जाता है. माना जा रहा है कि उनके निशाने पर सुशील कुमार मोदी थे जो हर दिन लालू परिवार के खिलाफ नए आरोप लगाए जा रहे हैं. साथ ही राजनीतिक तबके में उनकी इस चुप्पी को राजद सुप्रीमो के समर्थन के तौर देखा जा रहा है.

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक लालू परिवार पर लग रहे ताजा आरोपों को लेकर नीतीश के चुप्पी साधने के पीछे भी राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित देख रहे हैं. राज्य की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं, ह्नजो आरोप तेजस्वी और तेज प्रताप पर लगाए गए हैं, यही आरोप उनकी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ लगने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे तुरंत ही इस्तीफा ले लेते. लेकिन, उन्होंने इस मामले पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है.ह्व वे आगे बताते हैं, ह्नइसे हम इस संकेत के रूप में देख सकते हैं कि फिलहाल लालू के साथ बने रहने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है.ह्व सुरेंद्र किशोर राजनीतिक गलियारों में चल रही इस चर्चा पर भी अपनी सहमति जाहिर करते हैं कि लालू प्रसाद यादव का इन मामलों में उलझे रहना नीतीश कुमार के लिए अपने हिसाब से सरकार चलाने में मददगार साबित हो सकता है.

सुरेंद्र किशोर की इन बातों पर सुशील कुमार मोदी भी मुहर लगाते दिखते हैं. पिछले दिनों बातचीत में उन्होंने कहा, नीतीश कुमार मुकदमों में फंसे कमजोर लालू का साथ पसंद करेंगे. लालू कमजोर रहेंगे तो नीतीश के लिए सरकार चलाना आसान होगा. इससे लालू का सरकार में दखल कम हो जाएगा. लालू के बेटे घुटने टेककर नीतीश के सामने रहेंगे.

साल 2015 के बिहार चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत हासिल होने के बाद कई सारे सवाल उठे थे. इनमें सबसे बड़े सवाल यह था कि क्या नीतीश कुमार पहले की तरह अपने तरीके से शासन चला पाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सरकार में ज्यादा दखल तो नहीं होगा? इन सवालों के पीछे की वजह राजद का 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना था. राज्य में नई सरकार को लेकर में उठ रही इन आशंकाओं को देखते हुए राजद सुप्रीमो ने नतीजे वाले दिन (आठ नवंबर, 2015) को ही साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही नई सरकार विकास के लिए काम करेगी. इसके बावजूद राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह सहित अन्य नेता समय-समय पर सरकार में नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. जानकारों के मुताबिक ऐसे में लालू यादव के परिवार पर लगते आरोप नीतीश के लिए मनचाही मुराद की तरह आए हैं. वे इस प्रकरण का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं जिससे राजद बिना उन्हें परेशान किए उनके साथ बना रहे.

## महत्वाकांक्षा और मजबूरी

राज्य की राजनीति को करीब से देखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, नीतीश कुमार 2019 के चुनाव को देखते हुए भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए वे साझेदार के रूप में राजद का साथ नहीं छोड़ सकते. वे आगे कहते हैं, नीतीश भारतीय राजनीति में जब तक नरेंद्र मोदी के सबसे मजबूत विकल्प बने रहेंगे, वे लालू परिवार के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाकर सरकार और केंद्र में अपनी संभावनाओं को खतरे में डालने की भूल नहीं करेंगे. उनकी इस बात की पुष्टि बीते दिनों प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह की एक रिपोर्ट से भी होती है. इस रिपोर्ट में लालू परिवार के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज किया गया है.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# इस नए राष्ट्रपति की एक अनोखी कहानी है

**अभय शर्मा**

फ्रांस के लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवार इमानुएल माक्रों को अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है. 7 मई को हुए दूसरे दौर के चुनाव में पूर्व बैंकर माक्रों का मुकाबला घोर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन से था. माक्रों ने इस चुनाव में करीब 65 फीसदी मत हासिल किए जबकि पेन को उम्मीद से काफी कम मात्र 35 फीसदी वोटों से ही संतोष करना पड़ा.

फ्रांस का यह चुनाव कई राजनीतिक वजहों से तो चर्चा में है ही, इमानुएल माक्रों की प्रेम कहानी को लेकर भी यह चुनाव दुनिया भर में काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहा है. 39 वर्षीय माक्रों ने अपने से उम्र में 25 साल बड़ी महिला ब्रिजित तरोग्नयूक्स से शादी की है. इस समय ब्रिजित की उम्र 64 साल है. एक समय वे माक्रों की शिक्षिका थीं.

एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में माक्रों बताते हैं कि 1992 में उनकी प्रेम कहानी फ्रांस के शहर एमिंस के एक पब्लिक स्कूल से शुरू हुई थी जिसमें वे छात्र थे और ब्रिजित साहित्य और ड्रामा की टीचर थीं. एक ड्रामा में अभिनय करने के दौरान उनकी मुलाकात ब्रिजित से हुई थी. ड्रामा खत्म होने के बाद वे उन्हें साहित्य भी पढ़ाने लगी थीं. माक्रों के एक मित्र बताते हैं कि साहित्य की क्लास के दौरान ही दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई थी. इस मित्र के अनुसार इमानुएल माक्रों काफी अच्छी कविताएं लिखा करते थे जिस वजह से ब्रिजित उन पर विशेष ध्यान देने लगीं थी. वे माक्रों को कविता लिखने के लिए अपने घर बुलाती थीं. हाल ही में एक साक्षात्कार में ब्रिजित ने स्वीकार भी किया था कि वे 16 वर्षीय माक्रों के कविता लिखने की कला की कायल हो गई थीं और यही चीज उन्हें माक्रों के करीब ले आई थी.

करीब दो साल तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर 17 साल की उम्र में माक्रों ने अपनी 42 वर्षीय शिक्षिका के सामने अचानक प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रख दिया. फ्रांस की वरिष्ठ पत्रकार ऐनी फुलदा अपनी किताब इमानुएल माक्रों- ए परफेक्ट यंग मैन में लिखती हैं कि तीन बच्चों की मां ब्रिजित ने उस समय अपने बच्चों की वजह से शादी

करने से इनकार कर दिया लेकिन, उन्होंने माक्रों के प्यार को स्वीकार कर लिया.

फुलदा लिखती हैं कि उस समय माक्रों के माता-पिता और उनके मित्र यह समझते थे कि माक्रों अपनी शिक्षिका ब्रिजित की बेटी लेरिंस से प्यार करते हैं जो उस समय उनकी सहपाठी थीं और इसीलिए वे ब्रिजित के घर जाने को इतने उतावले रहते हैं. लेकिन, जब माक्रों ने अपने घरवालों को ब्रिजित से प्यार करने के बारे में बताया तो वे काफी ज्यादा नाराज हो गए. लाख समझाने के बाद भी न समझने पर घरवालों ने इमानुएल माक्रों को एमिंस शहर से दूर पेरिस पढ़ाई के लिए भेज दिया. फुलदा के मुताबिक ऐसा करने से पहले माक्रों के पिता ने ब्रिजित से भी अपने बेटे से न मिलने को कहा लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया था. माक्रों के पेरिस जाने के बाद इन दोनों की फोन पर लंबी-लंबी बातें हुआ करती थीं.

हालांकि, कई सालों तक अफेयर चलने के बाद भी इन दोनों ने तब तक शादी न करने का वादा किया था जब तक ब्रिजित के बच्चे और माक्रों खुद अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं. 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढाई पूरी करने के बाद इमानुएल माक्रों को फ्रांस के वित्त मंत्रालय में वित्त निरीक्षक की नौकरी मिली. इसके बाद 2006 में ब्रिजित ने अपने पहले पति को तलाक दिया और माक्रों से शादी कर ली.

ब्रिजित की सबसे छोटी बेटी और पेशे से वकील 33 वर्षीय टिफीन एक साक्षात्कार में माक्रों की तारीफ करते हुए बताती हैं कि उन्हें और उनके भाई-बहनों को शुरू से लगता था कि माक्रों उनकी मां से कभी शादी नहीं करेंगे. क्योंकि जब उन्होंने शादी का वादा किया था तो उनकी उम्र काफी कम केवल 18 साल थी. उन्हें लगता था कि माक्रों के मन में वही आकर्षण जो कम उम्र के लड़कों में होता है और वे वक्त के साथ चीजों को समझेंगे और उनकी मां को भूला देंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और माक्रों ने 10 साल बाद उनकी मां से आकर शादी की. वे कहती हैं कि उनकी मां के तलाक के बाद माक्रों के सामने शादी को लेकर कोई अड़चन नहीं थी लेकिन, फिर भी उन्होंने उनसे और उनके भाई-बहनों से इस बारे में खुलकर बात की और उनकी सहमति के बाद ही शादी की.

यूरोप के कई पत्रकार कहते हैं कि अगर इस तरह का मामला किसी और देश में होता तो शायद यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा होता और विरोधी पार्टियां इसे जमकर भुनातीं. लेकिन, फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा बिलकुल नहीं है. ये लोग इसकी कई वजहें भी बताते हैं.

सीएनएन से जुड़े फ्रांस के पत्रकार जिम बिटरमन कहते हैं कि फ्रांस के चुनावों में यह कोई मुद्दा बन ही नहीं सकता क्योंकि यहां के लोगों ने इससे कहीं बड़ी और गलत चीजें होती देखी हैं. उनके अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद राष्ट्रपति रहते हुए 41 वर्षीय अभिनेत्री जुली गाये के प्रेम में पड़ गए. वे इस प्रेम में इस कदर डूबे थे कि सबकुछ भूल कर रातों को स्कूटर पर इस अभिनेत्री के घर के चक्कर लगाते दिख जाते थे. इस प्रकरण के बाद ओलांद की पत्नी ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था. इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति जैक्स चिराक ने एक सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रेम संबंधों का खुलासा खुद ही कर दिया था.

जानकारों के मुताबिक इन सभी घटनाओं के सामने इमानुएल माक्रों का मामला तो कुछ भी नहीं है. साथ ही जिस ईमानदारी के साथ माक्रों ने हमेशा इस रिश्ते को स्वीकार किया उसने जनता के बीच उनकी छवि को बेहतर बनाने में मदद ही की है.

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of PDFCompressor

# अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद

नीतीश के बाद लालू प्रसाद - और दोनों की मन की बात सुनने के बाद महागठबंधन को लेकर अब सोनिया गांधी की भी सक्रियता देखी जा रही है जिसका मुख्य मकसद तो 2019 का आम चुनाव ही है, लेकिन तात्कालिक वजह राष्ट्रपति चुनाव है.

पक्ष की एकता की राह में सबसे बड़ी बाधा सत्ता ही रही है. सत्ता के खिलाफ ही विपक्ष को इकट्ठा होना होता है - और सत्ता की ख्वाहिश ही उसे साथ होने नहीं देती. ताजा त्रासदी तो ये है कि विपक्ष देश में महागठबंधन खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके पास सत्ता हासिल करने से अलग कोई एजेंडा नहीं है.

नीतीश के बाद लालू प्रसाद - और दोनों की मन की बात सुनने के बाद महागठबंधन को लेकर अब सोनिया गांधी की भी सक्रियता देखी जा रही है जिसका मुख्य मकसद तो 2019 का आम चुनाव ही है, लेकिन तात्कालिक वजह राष्ट्रपति चुनाव है.

## कांग्रेस करे अगुवाई

बिहार की तर्ज पर यूपी में महागठबंधन की कवायद फेल रही. असली राजनीतिक वजह जो भी

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

रही हो, यूपी में नीतीश कुमार ने जैसी शुरूआत की अंत उससे बिलकुल जुदा रहा. विपक्ष की ओर से अब बिहार जैसी ही कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है. यूपी से अलग बात इसमें ये है कि नीतीश के साथ साथ लालू प्रसाद भी खासे सक्रिय हैं - और दोनों इस बात पर सहमत भी हैं कि विपक्ष का हर हाथ कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला ले. नीतीश कई बार पहले भी कह चुके हैं कि चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए उसे इस लाइन पर अगुवाई भी करनी चाहिये.

### पटना से ही शुरु होगी कवायद

नीतीश की कोशिश गैर-बीजेपी दलों को एक मंच पर खड़ा करने की रही है - और उसी को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी चाहती हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाये. इस सिलसिले में फोन पर बात और मुलाकातों का सिलसिला जारी है जिसके लिए नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त बनी है - शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, एचडी देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव और उमर अब्दुल्ला. इसी में ओडीशा के नवीन पटनायक और एमके स्टालिन से लेकर तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं और एआईएडीएमके और शिवसेना जैसी पार्टियों को भी अपने पक्ष में तैयार करना है. शिवसेना से ज्यादा उम्मीद उसके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से है. विपक्ष को उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार भी वो साथी बीजेपी से अलग स्टैंड लेगी. बीजेपी के साथ शिवसेना के हालिया रिश्तों के चलते इसकी संभावना भी अधिक लग रही है.

### बड़ी बात होगी

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर अगर एनडीए को टक्कर दे पाया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी. साथ ही, इससे आगे का रास्ता भी खुलेगा और मालूम होगा कि असली चुनौतियां कहां छिपी हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है. वैसे अब तक जो बातें सामने आई हैं उनसे लगता है कि दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा पटना में होगी - गांधी मैदान ही नये महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का भी गवाह बनेगा, ऐसी संभावना है. लालू प्रसाद ने 27 अगस्त को पटना में सभी विपक्षी दलों की महारैली का ऐलान किया है.

प्रस्तावित रैली के लिए नाम दिया गया है - 'भाजपा भगाओ-देश बचाओ'. बिहार चुनाव से पहले वहां पर स्वाभिमान रैली हुई थी जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई थीं.

# कांग्रेस करे भी तो क्या..?

महागठबंधन के लिए राजी होना ऐसी स्थिति है कि विचारधारा पीछे छूट जाती है. ऐसे में या तो सत्ता का लालच या कोई ज्वलंत मसला या फिर अस्तित्व का संकट ही महागठबंधन खड़ा होने की शर्त होती है. जहां तक मुद्दों की बात है तो ये महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ है. बीजेपी के खिलाफ यानी उसके हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ और कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि वो विरोध करे तो किस आधार पर करे. क्षेत्रीय नेताओं में कोई सांप्रदायिकता के नाम पर तो कोई आरक्षण के नाम पर विरोध का झंडा बुलंद कर लेता है, लेकिन कांग्रेस इसमें फंस जाती है. नतीजा ये होता है कि विरोध के नाम पर उसे कुछ भी बोलना पड़ता है. सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी का बयान - खून की दलाली, ऐसी ही एक मिसाल है.

जो राजनीतिक हालात हैं उससे ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर वैसी ही स्थिति में पहुंच रही है जैसी वो 1996 से 1998 के दौरान रही. ये वो दौर रहा जब कांग्रेस का शासन तीन-चार राज्यों तक सीमित रहा. ये ठीक सोनिया गांधी के कमान अपने हाथ में लेने से पहले की बात है.

हाल के विधानसभा चुनाव बताते हैं कि सोनिया गांधी रूटीन की राजनीतिक गतिविधियों से दूर होना चाहती रहीं. इसकी बड़ी वजह उनका स्वास्थ्य माना जाता है. लेकिन उन्हीं चुनावों के नतीजों ने राहुल के नेतृत्व सवाल उठाने वालों को मौका दे दिया. संभव है, इसी नाते सोनिया को फिर से न चाहते हुए भी सक्रिय होना पड़ा हो.

कांग्रेस कहने को तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन संवैधानिक हकीकत ये है कि उसके पास विपक्ष के नेता का ओहदा भी नहीं है. ऐसे में लालू और नीतीश कांग्रेस के लिए हनुमान बन कर संजीवनी खोजने में मददगार साबित हो सकते हैं. लालू ने तो पहले भी सोनिया का सपोर्ट किया है. पेंच तभी फंसता है जब स्क्रीन पर राहुल गांधी आ जाते हैं.

कांग्रेस के लिए केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की ओर से बड़ा खतरा है ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पर वो उसके नेताओं को आगे बढ़ कर लपक ले रही है.

ऊपर से देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि राष्ट्रीय महागठबंधन के सेंटरस्टेज पर नीतीश कुमार ही हैं. लालू की भी इसमें दिलचस्पी इसलिए हो सकती है क्योंकि इससे तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का रास्ता साफ हो सकता है. पेंच एक बार फिर राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही फंसता है. या तो नीतीश भी किस्मत को कोसते हुए राहुल गांधी को नेता मान लें या फिर कांग्रेस के युवराज ही नीतीश को दूसरा मनमोहन मान कर मां सोनिया की तरह संतोष कर त्याग की नई मिसाल पेश करें. ले देकर यही वो व्यवस्था है जिसमें विपक्ष का अस्तित्व कायम रह सकता है, वरना मोदी-शाह और भागवत की तिकड़ी तो अपने मिशन पर निकल ही पड़ी है.

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of PDFCompressor

# आरएसएस-भाजपा संबंध मिथक बनाम वास्तविकता

**अरुण आनंद**

2014 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आने के साथ ही कई जगह यह कयास लगने आरंभ हो गए थे कि क्या नरेंद्र मोदी–अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच अब टकराव होगा। मोदी की लगातार कद्दावर होती छवि तथा उनके पुराने सहयोगी रहे अमित शाह के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद कई बार अटकलें लगाई गई कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को दरकिनार कर दिया जाएगा।

मई 2014 से लेकर अब तक लगातार कई राज्यों के विधानसभा चुनावों तथा स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के संदर्भ में इन अटकलों की पड़ताल करने की आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले ज्यादातर विश्लेषकों की आरएसएस के बारे में जो अवधारणा है वह सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। प्रचार से दूर रहने की नीति के कारण आरएसएस को लेकर कई आधारहीन धारणाएं भी पैदा हो गई हैं जिनमें से एक अवधारण यह है कि भाजपा व आरएसएस में एक दूसरे पर प्रभाव जमाने के लिए खींचतान चलती रहती है।

आरएसएस और भाजपा का आपसी संबंध ऐसा है कि एक दूसरे को दबाने का सवाल ही नहीं खड़ा हो सकता है। भाजपा में हर प्रदेश में अध्यक्ष के अलावा सबसे प्रमुख पद संगठन मंत्री का है जिसका दायित्व हमेशा आरएसएस के किसी प्रचारक के पास रहता है। अध्यक्ष अमूमन कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है और दोनों प्रमुख पदाधिकारी समन्वय से काम करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा के संगठन मंत्री का दायित्व का पद हमेशा से आरएसएस के किसी प्रचार के पास ही रहता है। यह परंपरा भाजपा के पूर्व संस्करण भारतीय जनसंघ के समय से चली आ रही है।

स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। केंद्र में मोदी के मंत्रिमंडल के लगभग सभी प्रमुख मंत्री आरएसएस के लंबे समय तक स्वयंसेवक रहे हैं और उनमें से कई पूर्व प्रचारक हैं। कमोबेश यही स्थिति भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मामले में भी है। भाजपा में राष्ट्रीय तथा प्रांत के स्तर पर संगठन के ज्यादातर प्रमुख पदों पर आरएसएस से लंबे समय तक जुड़े स्वयंसेवकों को ही दायित्व दिया गया है।

ऐसे में भाजपा बनाम आरएसएस तथा मोदी बनाम आरएसएस जैसे विवादों की कोई जगह मौजूदा सत्ता तंत्र में नहीं दिखती। सरकार तथा पार्टी के रोजमर्रा के काम–काज में आरएसएस कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन समय समय पर सरकार तथा पार्टी व आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों के बीच बातचीत तथा विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। जरूरत पड़ने पर आरएसएस अथवा उससे वैचारिक दृष्टि से जुड़े विविध संगठनों की ओर से राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सरकार व पार्टी को सुझाव भी दिए जाते हैं। इन्हें मानना या न मानना सरकार व पार्टी पर निर्भर है।

चुनावों में आरएसएस की क्या भूमिका रहती है इसे लेकर अक्सर कई प्रकार की खबरें मीडिया में सामने आती हैं। हर चुनाव से पहले कयास लगाए जाते हैं कि आरएसएस इस बार भाजपा के लिए कितना काम करेगा। सिद्धांत की बात करें तो आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसके स्वयंसेवक व पदाधिकारी सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं।

व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वैचारिक निकटता के कारण आरएसएस के स्वयंसेवक कई बार निजी स्तर पर भाजपा की मदद करते हैं। अपने क्षेत्र में लगातार सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने के कारण आरएसएस के स्वयंसेवकों का अपना एक प्रभाव क्षेत्र तो होता ही है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समान सोच रखने के कारण भाजपा को इस प्रभाव क्षेत्र का लाभ मिलता है।

लेकिन अपने गठन के लगभग 92 साल बाद भी आरएसएस का मुख्य अजेंडा सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना है। आज भी आरएसएस का यही मानना है कि राजनीति के माध्यम से समाज में स्थायी परिवर्तन संभव नहीं बल्कि यह केवल चरित्र निर्माण से ही हो सकता है और इसके लिए राजनीति से दूरी बनाए रखते हुए समाज के अन्य क्षेत्रों में सतत प्रयास करना आवश्यक है। इसलिए समय आ गया है आरएसएस बनाम भाजपा की अटकलों पर विराम लगाया जाए।

लेखक आरएसएस से जुड़े विषयों पर दो दशकों से शोध व लेखन कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र हैं। यह लेखक के अपने निजी विचार हैं। इससे संपादक का सहमत होना कोई जरुरी नहीं है।

# टाटा का हर नया कदम एक गलती बन गया

पुलकित भारद्वाज

वाहन कंपनियां आमतौर पर लोगों के ध्यान में तब आती हैं जब वे किसी सेगमेंट में नया वाहन लॉन्च करती हैं. लेकिन भारत के कार बाजार में एक ऐसी कंपनी भी है जिसे गाड़ियों से ज्यादा सेगमेंट लॉन्च करने के लिए जाना जाता है. देश की पहली यात्री कार इंडिका और सूमो जैसी दमदार मल्टी यूटिलिटी व्हीकल से लेकर दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो तक, भारत में अधिकतर सेगमेंट्स की पहल का श्रेय टाटा मोटर्स के नाम है.

इस भारतीय वाहन कंपनी का सफर देश की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था. टाटा मोटर्स की मूल कंपनी टाटा इंजिनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को) सन 1945 में अस्तित्व में आयी थी. उस जमाने में टेल्को को रेल के इंजन बनाने के लिए जाना जाता था. लेकिन यह कंपनी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहती थी. इसका सपना भारत की पटरियों के साथ यहां की सड़कों पर भी अपना आधिपत्य जमाने का था. इस दिशा में काम करते हुए टाटा ने व्यापारिक वाहनों के निर्माण की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया. 1970 आते-आते टेल्को इस श्रेणी के वाहन बाजार में शीर्ष पर आ गयी. आलम यह था कि सड़क पर हर तीन में से दो ट्रक टाटा के दिखाई देते थे. इस सफलता ने टाटा के सपने को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया.

लेकिन 1980 के बाद देश की अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी थीं. इसके चलते टाटा मोटर्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती गयी और इसके शेयर नीचे आते गए. आर्थिक तौर पर अपनी मजबूती और बाजार के शीर्ष पर स्थान बनाए रखने के लिए टाटा ने यात्री कारों के निर्माण की तरफ रुख करने का फैसला लिया. सन 1990 में टेल्को ने 1700 करोड़ रूपए का निवेश कर एक और कंपनी को खड़ा किया जो पूरी तरह से स्वदेशी यात्री कार बनाने के लिए समर्पित थी. इसी कंपनी को बाद में टाटा मोटर्स के नाम से जाना गया. टाटा मोटर्स बनने के बाद से ही साल दर साल अपनी नई गाड़ियों के साथ सेगमेंट और बाजार में दस्तक देती रही.

पिछले करीब ढाई दशक में टाटा ने कई कारें लॉन्च की हैं लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना था कि टाटा ने यह कदम उठाकर बड़ी गलती कर दी थी. हालांकि शुरूआत में इंडिका की रिकॉर्ड सेल ने इन सभी पूर्वानुमानों को एक बार तो गलत साबित कर दिया. लेकिन धीरे-धीरे वे सभी आशंकाएं सही साबित होने लगीं. समय के साथ टाटा हर बार अपने ही चालू किये सेगमेंट में पिछड़ने लगी और दूसरी कंपनियां उसका फायदा उठाने में सफल रहीं. हाल ही में खबर आई है कि अप्रैल 2017 में टाटा मोटर्स की बिक्री में बीते साल के मुकाबले 21 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.

ऐसे में यह निश्चित तौर पर सोचने का विषय था कि देश की शीर्ष कंपनी जिसके पास तमाम संसाधनों के साथ गाड़ियों की इतनी बड़ी रेंज मौजूद है, वह इस तरह हर बार पिछड़ क्यों जाती है?

यदि ऐसा सिर्फ एक या दो बार होता तो इसे इत्तेफाक माना जा सकता था. लेकिन जिस तरह टाटा हर बार उस पायदान से नीचे खिसकती गयी (जहां उसे होना चाहिए था) उसने यह साबित किया कि कहीं ना कहीं यह कंपनी अपने ही देश के ग्राहकों को समझने में बड़ी चूक कर रही है. विशेषज्ञ इस चूक के पीछे कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं.

टाटा को इस वाहन श्रेणी में अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने के पीछे जानकार इसकी महत्वाकांक्षाओं को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं. उनका मानना है कि टाटा सबसे छोटी कार नैनो से लेकर हेक्सा जैसी क्रॉसओवर तक हर सेगमेंट में अपनी उपस्थिति चाहती है. इसके अलावा व्यापारिक वाहनों के कई बड़े सेगमेंट में भी टाटा ने अपने पैर फंसा रखे हैं, जो कि टाटा का प्रमुख बाजार है. ऐसे में ज्यादा सेगमेंट में उलझने के कारण टाटा मोटर्स अपनी हर गाड़ी की परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर पाती है और इसकी गाड़ियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है. आंकड़ों पर ध्यान दें तो बाजार में टाटा की तुलना में कहीं ज्यादा यात्री गाड़ियां मारूति की हैं. लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनमें से अधिकतर गाड़ियां सिर्फ दो ही सेगमेंट में हैं. इसके चलते मारूति अपनी गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान देने के साथ इसका सीधा फायदा उठाने में सफल रहती है जबकि टाटा इस मामले में असफल मानी जाती है.

## छवि

अधिकतर लोगों के जेहन में टाटा की छवि लोडिंग और टैक्सी वाहन बनाने से जुड़ी हुई है. ऐसे में भारत जैसे देश में जहां आज भी गाड़ियां विशेषज्ञों की बजाय रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछ कर ली जाती है वहां टाटा को इस बात का नुकसान उठाना पड़ता है. कई बार देखने में आता है कि जो लोग गाड़ियों के बारे में कुछ खास नहीं जानते, वे भी सिर्फ इसी छवि के चलते टाटा की गाड़ी न खरीदने की सलाह देकर ग्राहक का ध्यान दूसरे विकल्पों की तरफ ले जाते हैं.

इसके अलावा टाटा का भारतीय कंपनी होना भी कभी-कभी इसके लिए घाटे का सौदा साबित होता है. लोगों के बीच एक धारणा यह भी है कि विदेशी गाड़ियों की परफॉर्मेंस और उनके फीचर्स अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं. ऐसे में आम ग्राहक टाटा की बजाय बाहरी कंपनियों की गाड़ी खरीदना ज्यादा उचित समझता है.

## रणनीति में कमी

कई जानकारों का मानना है कि भारत की होने के बावजूद टाटा देश के बाजार को कई बार नहीं समझ

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

पाती और गलत रणनीतियां बना देती है. उदाहरण के तौर पर भारत जैसे देश में जहां आज भी कार को सुविधा से ज्यादा शान का प्रतीक समझा जाता है वहां टाटा ने नैनो को देश की सबसे सस्ती कार बताते हुए प्रमोट किया. जानकारों के मुताबिक कोई अपने नाम के साथ सबसे सस्ती गाड़ी का टैग नहीं जोड़ना नहीं चाहता. इस गलती का सीधा खामियाजा टाटा को उठाना पड़ा जिसे बाद में खुद रतन टाटा ने भी स्वीकार किया.

इसके अलावा जानकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों की मार्केटिंग और उनके विज्ञापन में भी संतुलन नहीं बना पाती है. नई गाड़ियों की बात की जाए तो मध्यमवर्गीय परिवार के बजट को ध्यान में रखते हुए तैयार हुई टिएगो के विज्ञापन के लिए टाटा ने लियोनल मेसी जैसी शख्सियत को चुना. जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस चमकते खिलाड़ी की फेसवेल्यू बहुत है, लेकिन भारत के मध्यमवर्गीय परिवारों को मेसी उतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं. उनका मानना है कि मेसी से काफी कम कीमत पर टाटा को कोई ऐसा चेहरा मिल जाता जो भारत के मध्यम वर्ग में ज्यादा जाना-पहचाना होता और उन्हें ज्यादा प्रभावित कर पाता. वहीं कई लोगों की यह शिकायत भी है कि अपने सेगमेंट में हाई फीचर्स से लैस जेस्ट के लिए टाटा ने उतना प्रचार नहीं किया जिससे इसे एक सेमीलग्जरी गाड़ी की तरह पेश कर लोगों को लुभाया जा सकता था.

## लंबे समय ढर्रे में कोई बदलाव नहीं

कहा जाता है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में एक है. जहां बदलाव कम समय में ही आ जाता है. जबकि ग्राहकों की मानें तो टाटा ने सालों तक अपनी गाड़ियों में कोई खास बदलाव नहीं किया. उसका अधिकतर ध्यान पुरानी गाड़ियों को अपडेट करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां लॉन्च करने में लगा रहा. यही कारण था सूमो जैसी लोगों की पसंदीदा गाड़ी भी बदलाव की रेस में दूसरों से पीछे रह गई और (टोयोटा) इन्नोवा और (महिंद्रा) बोलेरो जैसी गाड़ियों ने इसकी जगह ले ली.

जानकारों के मुताबिक डिजाइन के मामले में भी टाटा दूसरी कंपनियों से बहुत पीछे रह जाती है. इंडिका जैसी हैचबैक कार से लेकर आरिया जैसी क्रॉसओवर तक टाटा की सभी गाड़ियों का लगभग एक सा लुक आता है और ग्राहकों को एक बड़े वर्ग को इसलिए भी टाटा की गाड़ियों से हिचक होती है. हालांकि टिएगो और हाल में टिगोर के लांच से टाटा ने इस मोर्चे पर बड़ा बदलाव करने की कोशिश की है

## ज्यादा मेंटनेंस और कीमत

अक्सर लोग टाटा की गाड़ियों की मेंटेनेंस को लेकर शिकायत करते हैं. एक यह भी बड़ा कारण है कि सामान्य ग्राहक टाटा की कार खरीदने से बचता है. देश का पहला स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सफारी अपने दमदार लुक और तमाम खूबियों के बाद भी इसी धारणा के चलते अपेक्षाकृत प्रचलन में नहीं है और महिंद्रा स्कोर्पियो इस बात का सीधे फायदा उठाती नजर आती है.

मेंटेनेंस के अलावा ग्राहकों को टाटा से एक शिकायत और है और वह है इसकी कीमत. लोगों को लगता है कि जब कोई गाड़ी देश में बन रही है तो सस्ती ही होगी. ऐसे में एक ही सेगमेंट में किसी देशी गाड़ी की विदेशी कंपनियों की तुलना में बराबर या उससे ज्यादा कीमत चुकाना ग्राहकों को ज्यादती लगती है. लेकिन जानकारों के मुताबिक सच्चाई यह है कि भारत में विनिर्माण के चलते कई बार संसाधनों की लागत ज्यादा बैठती है और वाहन की कीमतें बढ़ जाती है. ऐसा ही कुछ टाटा की बहुप्रतीक्षित क्रॉसओवर आरिया के मामले में देखने को मिला था. इस गाड़ी को टाटा ने इनोवा की टक्कर में उतारा था लेकिन ज्यादा कीमत के कारण ग्राहकों ने इस शानदार गाड़ी को खारिज कर दिया था. फिलहाल इस यदि हेक्सा की बात की जाए तो फीचर्स के लिहाज से टाटा ने इस गलती को सुधार लिया है.

## ग्राहकों के प्रति लापरवाही

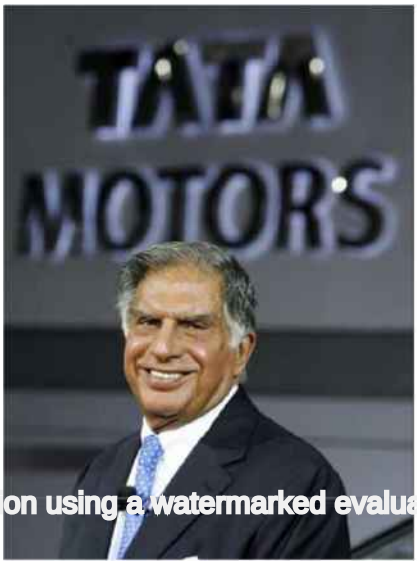

टाटा से जुड़ चुके ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि यह कंपनी सर्विस आफ्टर सेल देते समय ह्यचलता हैह्न जैसा रूख अपना लेती है. यह लोगों को कतई गवारा नहीं होता. गौर करने वाली बात यह भी है कि दूसरी अधिकतर कंपनियों से लगभग एक सा आर्थिक वर्ग जुड़ा होता है क्योंकि उनके पास




चुनिंदा सेगमेंट होते हैं. लेकिन टाटा मोटर्स के साथ ऐसा नहीं है. इस कंपनी से जुड़े ग्राहकों के वर्ग में इसकी गाड़ियों की ही तरह एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है. लखटकिया नैनो से लेकर सबसे ज्यादा टैक्सी में चलने वाली इंडिका-इंडिगो सहित सफारी और आरिया तक को खरीदने वाले ग्राहक टाटा के सर्विस सेंटर आते हैं. ऐसे में छोटी गाड़ियों के मालिकों को लगता है कि सर्विस के दौरान उनकी गाड़ियों की उपेक्षा की जा रही है. जबकि सेंटर पर एकसमान प्रतिक्रिया के कारण बड़ी गाड़ी के मालिकों के मन में अलग तरह की शिकायतें पैदा होती हैं.

ऐसे में कई ग्राहक और जानकार भी सुझाव देते हैं कि टाटा मोटर्स को कम से कम दो कैटेगरी के सर्विस सेंटर बनाने चाहिए. इसका पहला फायदा तो यह होगा कि वर्तमान सेंटरों से गाड़ियों का भार कम हो जाएगा. और दूसरे हर वर्ग के ग्राहक पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा जिससे लोगों का असंतोष कम होगा.

## आवाज और कम रीसेल वैल्यू

टाटा मोटर्स की गाड़ियों के साथ ग्राहकों को कम गुणवत्ता की शिकायत भी रहती है. इसमें ज्यादा पैनल गैप से लेकर प्लास्टिक तक तमाम चीजें शामिल हैं. कई शिकायत करते हैं कि टाटा की गाड़ियों को खरीदने के कुछ ही समय के अंदर उनमें खटर-पटर होने लगती है. हालांकि यह एक सामान्य समस्या है जो दूसरी कंपनियों के साथ भी हो सकती है, लेकिन टाटा के साथ यह कुछ ज्यादा ही है. साथ ही जब पहले से किसी कंपनी को लेकर ग्राहकों के मन में संशय हो तो ऐसे में छोटी से छोटी कमी भी उस कंपनी के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए काफी रहती है. इसके अलावा टाटा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू कम होने की भी शिकायत होती है जो कि उनके न खरीदे जाने की एक और प्रमुख वजह बन जाती है.

एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से भारत के कार बाजार में बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से अगले एक दशक बाद विश्व में सर्वाधिक कारों की खपत यहीं होगी. ऐसे में बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए टाटा मोटर्स को अपनी नीतियों से लेकर गाड़ियों की गुणवत्ता में बदलाव की सख्त जरूरत है. हालांकि टाटा की नई गाड़ियों जैसे टिएगो, टिगोर जेस्ट या हेक्सा की तरफ नजर डालें तो लगता है कि टाटा अब इस दिशा में पहले से ज्यादा गंभीरता बरत रही है. अब देखने वाली बात यह है कि नई कारों के साथ टाटा फिर नई छलांग लगाएगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी ग्राहक जल्द ही टाटा को टाटा कह देंगे.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# 1971 के राष्ट्रपति

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# आंकड़े किसके करीब

**पीयूष पांडे**

1971 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त देश की कुल आबादी 54.81 करोड़ थी. वहीं 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश की आबादी बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई है. 2017 में अभी अनुमान है कि देश की आबादी 128 करोड़ से अधिक है. इसका मतलब यह हुआ कि बीते 46 साल में देश की आबादी तकरीबन ढाई गुना हो गई. इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले जनप्रतिनिधियों के मतों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा रहा है. यानी कुछ ही दिनों बाद होने वाला राष्ट्रपति चुनाव भी 46 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर ही होने वाला है.

अगर आधार वर्ष को 1971 के बजाए 2011 कर दिया जाए तो 40 सालों में बढ़ी आबादी को देखते हुए कई राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और कुल मतों में उनकी हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी. संविधान के जानकारों का मानना है कि 1971 की आबादी के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव करवाए जाने से इस चुनाव में उन राज्यों को वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा जिनकी आबादी इस दौरान दूसरे राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ी है.

दरअसल, संविधान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनप्रतिनिधियों के मतों के निर्धारण को लेकर यह साफ था कि यह काम सबसे नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगा. इसलिए 1952 का राष्ट्रपति चुनाव 1951 की जनगणना के आधार पर हुआ. जबकि 1961 की जनगणना के आंकड़े समय पर नहीं उपलब?ध नहीं होने की वजह से 1962 में राष्ट्रपति का चुनाव भी 1951 की जनगणना के आधार पर ही हुआ. इसके बाद 70 के दशक में हुए राष्ट्रपति चुनावों का आधार 1971 की जनगणना बनी.

1971 की जनगणना को आधार बनाकर ही लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हुआ. 2004 तक के आम चुनाव उसी परिसीमन के आधार पर हुए और इस बीच हुए विधानसभा चुनावों का आधार भी 1971 की आबादी के आधार पर हुआ परिसीमन ही रहा. इस दौरान हुए सभी राष्ट्रपति चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर ही होते रहे. जबकि संविधान में यह प्रावधान था कि सबसे नई जनगणना को आधार बनाया जाएगा. लेकिन परिसीमन का आधार पुराना होने की वजह से राष्ट्रपति चुनाव भी पुराने आधार पर ही होता रहा. जब इस गड़बड़ी की ओर कुछ लोगों ने 2001 में सरकार का

एनडीए और यूपीए के बीच राष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. आंकड़े कह रहे हैं कि राष्ट्रपति एनडीए का होगा. या कहें, जिसे बीजेपी चाहेगी, वो राष्ट्रपति बनेगा. लेकिन, राजनीतिक गतिविधियां कह रही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस सीधी हार मानने के मूड में नहीं है.

पहले आंकड़ों के आइने में राष्ट्रपति चुनाव का खेल समझ लें-

राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट 11,04,546 हैं. एनडीए के तमाम दलों के विधायक-सांसद के कुल वोटों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा है 5,37,683, यानी कुल वोटों के 48.64 फीसदी. यूपीए के पास हैं 3,91,739 यानी 35.47 फीसदी और अन्य के पास हैं 1,44,302 यानी13.06 फीसदी.

कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की सत्ता से रुठे वो दल जो ना तो एनडीए में हैं और ना ही यूपीए में, वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के साथ आ सकते हैं. और अगर ऐसा होता है तो 13.06 फिसदी वोट विपक्ष के साथ जुड़कर एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे.

48.64 % = 35.47% + 13.06 % = 48.53 %एनडीए = यूपीए + अन्य

लेकिन फिर भी देखें तो अगर समूचा विपक्ष पूरी तरह एकजुट हो जाए तो भी वो एनडीए को मात नहीं दे सकता. लेकिन विपक्ष एकजुट होगा तो अंतर सिर्फ 0.11 फीसदी या कहें 1642 वोट का ही होगा.

यानी राष्ट्रपति चुनाव की बिसात पर हर मोहरा बीजेपी के हिसाब से चला तो उसकी जीत में कहीं कोई शक नहीं है. लेकिन-बैकफुट पर पहुंची यूपीए इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहती लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक तरफ यूपीए के सहयोगियों को एकजुट करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ यह कोशिश भी है कि एनडीए से कोई घटक टूट जाए. और एनडीए में जिस एक दल के टूटने की थोड़ी सी आशंका है वो है शिवसेना. राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के पास 2.34 फीसदी मत हैं यानी अगर यूपीए और अन्य के साथ शिवसेना भी मिल जाए तो बाजी एनडीए के हाथ से छिटक सकती है.

लेकिन तमाम नाराजगियों के बावजूद उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में खुलेतौर पर बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध करने का कोई संकेत अभी नहीं दिया है. वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जरुर ये संकेत दिए हैं कि वो राज्य के हित में बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन दे सकती है. टीआरएस के पास 1.99 फीसदी मत हैं.

यूं तो विपक्ष की तरफ से शरद पवार, शरद यादव, मुलायम सिंह से लेकर मनमोहन सिंह और मीरा कुमार तक के नाम दौड़ में हैं, लेकिन पहला सवाल तो आपस में सहमति का है. क्योंकि एक नाम पर ठोस सहमति बनने के बाद ही ऐसे हालात बन सकते हैं कि विपक्ष एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती दे पाए.

दरअसल, बैकफुट पर होते हुए भी अगर सोनिया गांधी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं तो मतलब साफ है. 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस देख लेना चाहती है कि कौन सी पार्टी किस तरफ खड़ी है? यानी एक सीधी लकीर सत्ता और विपक्ष के बीच राष्ट्रपति चुनाव के आसरे खींची जाएगी. और अगर विपक्ष बुरी तरह बंटता दिखा या कहें नाम को लेकर विपक्ष में ही घमासान मचा तो कांग्रेस तुरुप का इक्का चलते हुए प्रणव मुखर्जी का नाम ही दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित कर सकती है.

प्रणव मुखर्जी के नाम का विरोध कर पाना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रणव मुखर्जी ने जिस तरह बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है उसमें उनका विरोध कभी बीजेपी कर नहीं पाई अलबत्ता प्रधानमंत्री ने मौके-बेमौके प्रणव मुखर्जी की खुलकर तारीफ ही की. इस बीच बीजपी और एआईएडीएमके ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं तो उनका रुख भी साफ कर देगा कि विपक्ष के दांव में कितना दम है. गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव 25 जुलाई से पहले होने हैं क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है. इस बीच, इतना जरुर है कि विपक्ष की कोशिशों ने राष्ट्रपति चुनाव को दिलचस्प बनाना शुरू कर दिया है.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ध्यान खींचना कराना चाहा तो उस वक्त केंद्र की सत्ता पर काबिज अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने संविधान संशोधन करके यह तय कर दिया कि 2026 तक होने वाले सभी राष्ट्रपति चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर ही होंगे. जबकि उस वक्त यह मांग की जा रही थी कि बढ़ती आबादी को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव का आधार भी नई जनगणना के आंकड़ों को बनाया जाए.

अब सवाल यह उठता है कि इसके बावजूद वाजपेयी सरकार इसके उलट संविधान संशोधन क्यों लाई? इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के महासचिव रहे सुभाष कश्यप बताते हैं, उस वक्त जब राष्ट्रपति चुनावों के प्रावधानों में बदलाव की बात चली तो यह बात सामने आई कि नया आधार वर्ष लेते ही राष्ट्रपति चुनाव में तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों के मतों की हिस्सेदारी घट जाएगी और उत्तर भारत के कुछ राज्यों के मतों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी. इसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों ने केंद्र सरकार से यह कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण वाले कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सफलता से किया है इसलिए नया आधार वर्ष लेने से हमारे साथ अन्याय हो जाएगा क्योंकि मतों में हमारी हिस्सेदारी कम हो जाएगी. वे आगे बताते हैं, इन राज्यों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का काम सफलता से करने का पुरस्कार उन्हें इस रूप में मिलना चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव का आधार वर्ष पुराना ही रखा जाए. इसलिए उस समय की केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके न सिर्फ पुराने आधार वर्ष को ही बनाए रखने का फैसला किया बल्कि यह भी प्रावधान कर दिया कि 2026 तक के चुनाव ऐसे ही होंगे.

जानकारों के मुताबिक उस वक्त केंद्र सरकार के इस फैसले का ज्यादा विरोध इसलिए भी नहीं हुआ कि तब तक विधायकों और सांसदों का निर्वाचन भी 1971 के परिसीमन के आधार पर ही हो रहा था. लेकिन 2008 से विधानसभाओं के चुनाव नए परिसीमन के आधार पर शुरू हुए. नए परिसीमन के लिए आधार बनी 2001 की जनगणना. 2009 का लोकसभा चुनाव भी नए परिसीमन के आधार पर हुआ. इस आधार पर होना तो यह चाहिए था कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी 2011 को न सही 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाता. क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में मत डालने वाले ज्यादातर जनप्रतिनिधि 2001 की जनगणना के आधार पर हुए परिसिमन के तहत निर्वाचित हुए हैं. लेकिन सरकारी स्तर पर राष्ट्रपति चुनाव में व्याप्त इस खामी को दूर करने के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं हुई.

राष्ट्रपति चुनाव कराने का जिम्मा भी चुनाव आयोग के पास होता है. तो क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति चुनावों के आधार वर्ष में बदलाव का निर्णय ले? जानकारों का मत है कि इस बारे में चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं और नए आधार वर्ष के लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ेगा. संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सीके जैन बताते हैं, 2002 में हुए संविधान संशोधन में 2026 तक के लिए आधार वर्ष 1971 तय कर दिया गया है. अब अगर नए परिसीमन का आधार यानी 2001 की जनगणना को राष्ट्रपति चुनाव का भी आधार बनाना है तो इसके लिए संविधान में फिर से संशोधन करना होगा.

यह मुद्दा 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के समय भी उठा था. इस बाबत सोसाइटी फॉर एशियन इंटीग्रेशन ने चुनाव आयोग के पास शिकायत की थी. इस गड़बड़ी की वजह से हो रहे भेदभाव की ओर ध्यान दिलाते हुए संस्था ने अपनी शिकायत में लिखा था, ह्यबिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अनदेखी करके दक्षिण भारतीय राज्यों के विधायकों के मतों को अधिक महत्व मिलना जनप्रतिनिधित्व की जमीनी हकीकतों के अनुरुप नहीं है. संस्था ने इस शिकायत की एक प्रति जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव को दी और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. उस वक्त शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी थे. सूत्र बताते हैं कि जब शरद यादव ने यह मामला राजग की बैठक में उठाया तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह संशोधन तो अपनी ही सरकार ने किया था इसलिए इस मामले को लोगों के बीच उठाना ठीक नहीं है. भाजपा नेताओं



ने राष्ट्रपति चुनाव पर कई मोर्चे पर चल रही लड़ाइयों का हवाला देते हुए शरद यादव को यह सलाह दी कि एक नया मोर्चा खोलने का यह सही वक्त नहीं है. इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर भाजपा और जदयू दोनों अलग-अलग राह चल पड़े और यह मामला जहां था वहीं रह गया.

संविधान और राजनीति के जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया में व्याप्त इस खामी का असली प्रभाव उस वक्त दिखेगा जब कभी दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हो. इस बार ?अगर विपक्ष कोई साझा उम्मीदवार उतार दे और राजग खेमे में कोई मामूली सेंध भी लगा दे तो फिर इस खामी का असर तुरंत दिख सकता है. क्योंकि कांटे की टक्कर की स्थिति में कुछ सौ वोट भी बने खेल को बिगाड़ने और बिगड़े खेल को बनाने की कुव्वत रखते हैं. ऐसी स्थिति पैदा होने पर वह उम्मीदवार फायदे में रहेगा जिसे दक्षिण भारत के राज्यों के विधायकों का समर्थन हासिल हों. जबकि उत्तर भारतीय राज्यों के विधायकों के समर्थन वाला उम्मीदवार घाटे में रहेगा.

1971 की आबादी के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव में पड़ने वाले कुल मतों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की हिस्सेदारी क्रमशः 4.69 फीसदी, 15.25 फीसदी और 7.65 फीसदी है. जबकि अगर 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाए तो इन तीनों राज्यों की कुल मतों की संख्या तकरीबन दोगुनी हो जाएगी और हिस्सेदारी बढ़कर क्रमशः 5.5 फीसदी, 16.19 फीसदी और 8.08 फीसदी हो जाएगी. नया आधार वर्ष तय होने के बाद घाटे में रहने वाले तीन प्रमुख राज्य होंगे तमिलनाडु और केरल. 1971 की जनगणना के हिसाब से इन राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 7.49 फीसदी और 3.87 फीसदी थी. जो 2001 की जनगणना के आधार पर घटकर क्रमशः 6.04 फीसदी और 3.09 फीसदी रह जाएगी.

सुभाष कश्यप कहते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाना संविधान के एक व्यक्ति-एक वोट की मूल भावना के खिलाफ है. राष्ट्रपति चुनाव के मतों में जिन राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ रही है उन्हें सिर्फ यह कहकर इससे वंचित रखना उनके साथ अन्याय है कि उन्होंने आबादी नियंत्रण के कार्यक्रम ठीक से नहीं चलाए. अगर आबादी नियंत्रण ही आधार है तो फिर उन राज्यों के सांसदों की संख्या भी बढ़ा दीजिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को अच्छे से लागू किया है.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# पत्रकारिता जान की बाजी..

## पत्रकारिता..

जानलेवा साबित हो रही है. पूरे विश्व में कई देशों में पत्रकारों के हालात बेहद बदतर हैं. दिन दहाड़े उनके कत्ल हो रहे हैं. क्या पत्रकार की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है. इस मामले में भारत 136वां स्थान रखता है. भारत पत्रकारों के लिए 10 सबसे असुरक्षित देशों में अपनी जगह बनाता है. 1992 से 2017 के बीच देश में 40 पत्रकारों की हत्या हुई है और यही अधिकारिक आंकड़े हैं. इन सबसे परे प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है... आश्चर्य है.

## खराब शुरुआत

अभी 2017 का आधा साल भी नहीं गुजरा और...



**8 पत्रकारों** को दुनियाभर में मार डाला गया

*जिसमें से*

**5** राजनीति कवर करते थे

**4** क्राइम कवर करते थे

**2** युद्ध कवर करते थे

**1** करप्शन कवर करते थे

*आंकड़े 8 से भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि कई पत्रकारों के पास एक से ज्यादा बीट होते हैं*



## फिसला भारत

**#136वें**

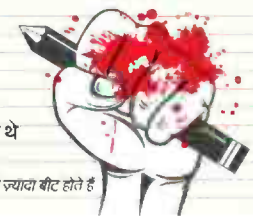

पायदान पर है भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (PFI) 2017 की 180 देशों की रैंकिंग सूची में

**3 स्थान की गिरावट आई है** पिछले साल की तुलना में

*PFI के अनुसार, भारत में प्रेस की आजादी के बीच ये कुछ खास चुनौतियां हैं*

- गुनाह दबाने के लिए पत्रकारों के खिलाफ़ ऑनलाइन मुहिम चलाना
- देशद्रोह का मामला लगाने की धमकी
- कश्मीर जैसे कई संवेदनशील जगहों पर काम करने में कठिनाई
- सरकारी नियंत्रण का बढ़ना, इंटरनेट सेंसरशिप आदि



## पड़ोसियों से टक्कर?

भारत पत्रकारिता के लिए उपयोगी माहौल देने के मामले में पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर स्थिति में है

*PFI रैंक / देश*




## ये भी असुरक्षित हैं

भारत पत्रकारों के लिए दुनिया के 10 सबसे असुरक्षित देशों में शुमार है (1992 से 2017 के बीच)

| देश | मारे गए पत्रकारों की संख्या |
|---|---|
| इराक | 179 |
| सीरिया | 108 |
| फीलिपींस | 78 |
| सोमालिया | 62 |
| अल्जीरिया | 60 |
| पाकिस्तान | 60 |
| रूस | 56 |
| कोलंबिया | 47 |
| भारत | 40 |
| मेक्सिको | 40 |

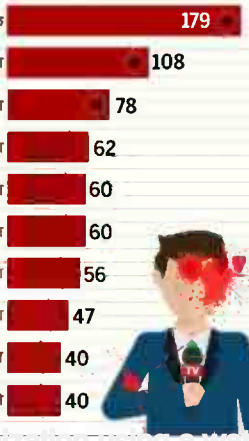



## ख़तरनाक बीट

भारत में ज़्यादातर वे पत्रकार मारे गए जिनके पास राजनीति और करप्शन जैसे अहम बीट थे

*जिसमें से*

- 50% राजनीति कवर करते थे
- 40% करप्शन कवर करते थे
- 25% क्राइम कवर करते थे
- 23% बिज़नेस कवर करते थे
- 20% मानव अधिकार कवर करते थे
- 5% युद्ध

*आकड़ो में 100 से ज्यादा ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास एक से ज्यादा बीट थी*

## मर्डर करने वाले संदिग्ध

*कत्ल किए गए पत्रकार*

- 48% राजनीतिक ग्रुप की ओर से कत्ल किया गया
- 20% आपराधिक ग्रुप द्वारा
- 10% सरकारी अधिकारियों द्वारा
- 8% स्थानीय निवासियो द्वारा
- 5% अर्द्धसैनिक ग्रुप द्वारा
- 13% अज्ञात

*आकड़े 100% से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि एक समान मामले में एक से अधिक ग्रुप शामिल रहे*

स्रोत: Committee for Protection of Journalists, Press Freedom Index

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# नेकी की सीख देता है रमज़ान

भारत में कई संस्कृतियों का मेल है। सभी संस्कृतियों की अपनी मान्यतायें हैं लेकिन सभी का मकसद प्रेम और करुणा ही हैं। बस निभाने का तरीका अलग-अलग हैं इसलिए भारत में कई त्यौहार मनायें जाते है। कई नव वर्ष हमारे देश में मनाये जाते हैं साथ ही एक से अधिक कैलंडर भी हमारे देश में होते हैं। सभी धर्मो के अपने अलग महीने होते हैं, उसमे कई परंपरायें सम्मिलित होती हैं। कई मान्यतायें भी शामिल होती हैं लेकिन सभी का उद्देश्य खुशी औए एकता होता हैं। ऐसे ही रमजान का अपना एक महत्व होता हैं, जो इस्लामिक देशो में बड़े जोरो शोरो ने मनाया जाता हैं। भारत में भी मुस्लिम सभ्यता हैं। यहाँ भी रमजान बड़े उत्साह से मनाया जाता हैं।

## क्या हैं रमजान ?

यह मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत ही महान महिना होता है, जिसके नियम बहुत कठिन होते हैं, जो इंसान में सहन शीलता को बढ़ाते हैं। रमजान का महिना बहुत ही पवित्र माना जाता हैं, यह इस्लामिक केलेंडर के नौवे महीने में आता हैं। मुस्लिम धर्म में चाँद का अत्यधिक महत्व होता हैं। इस्लामिक कैलेंडर में चाँद के अनुसार महीने के दिन गाने गाये जाते हैं, जो कि 30 या 29 होते हैं, इस तरह 10 दिन कम होते जाते हैं जिससे रमजान का महिना भी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक प्रति वर्ष 10 दिन पहले आता हैं। रमजान के महीने को बहुत ही पावन माना जाता हैं। रमजान अपने कठोर नियमो के लिए पुरे विश्व में जाना जाता हैं। रमजानके दिनों की चमक देखते ही बनती हैं पूरा महिना मुस्लिम इलाको में चमक-दमक एवम शोर शराबा रहता हैं। सभी आपस में प्रेम से मिलते हैं। गिले शिक्वे भुलाकर सभी एक दुसरे को अपना भाई मानकर रमजान का महिना मनाते हैं।

## रमजान का इतिहासः

इस पाक महीने को शब-ए-कदर कहा जाता हैं। मान्यता यह हैं कि इसी दिन अल्लाह ने अपने बन्दों को कुरान शरीफ से नवाजा था। इसलिए इस महीने को पवित्र माना जाता हैं और अल्लाह के लिए रोजा अदा किया जाता है, जिसे मुस्लिम परिवार का छोटे से बड़ा सदस्य पूरी शिद्दत से निभाता हैं।

## कैसे किया जाता है रोजा ?

रमजान में रोजा किया जाता हैं जिसे अल्लाह की इबादत कहते हैं। रोजा करने के नियम होते हैं :

**सहरीः** सहरी का बहुत महत्व होता हैं इसके लिए सुबह सूरज निकलने के देड़ घंटे पहले उठना होता हैं और कुछ खाने के बाद ही रोजा शुरू होता हैं। इसके बाद पूरा दिन कुछ खा या पी नहीं सकते।

**इफ्तारः** शाम को सूरज डूबने के बाद कुछ समय का अंतराल रखते हुए रोजा खोला जाता हैं। जिसका समय निश्चित होता हैं।

**तरावीहः** रात को एक निश्चित समय पर तरावीह की नमाज अदा की जाती हैं यह समय लगभग 9 बजे का होता हैं। साथ ही मजिदो में कुरान पढ़ी जाती हैं।

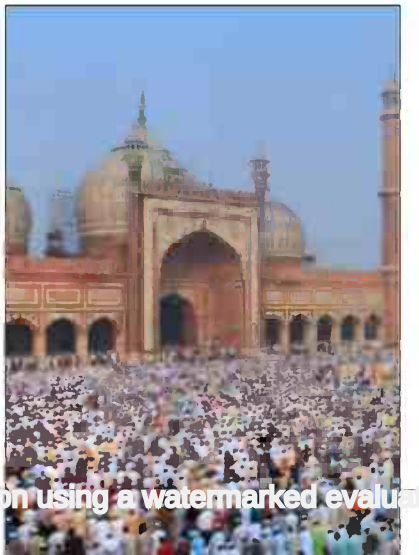

ऐसा पुरे रमजान होता हैं इसके बाद चाँद के अनुसार 29 या 30 दिन बाद ईद का जश्न मनाया जाता हैं।

## रमजान के नियम :

रमजान के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। कहा जाता हैं इससे इंसान और अल्लाह के बीच की दुरी कम होती हैं। इन्सान में धर्म के प्रति भावना बढ़ती हैं साथ ही अल्लाह पर विश्वास पक्का होता हैं। रमजान ने एकता की भावना बढ़ती हैं।

रमजान में रोजा रखा जाता हैं जिसमे अल्लाह का नाम लिया जाता हैं। नमाज अदा की जाती हैं साथ ही कलाम भी पढ़ा जाता हैं।

## गलत आदतों से दूर रहे :

रमजान के पुरे महीने गलत आदतों से दूर रहने की हिदायत दी जाती हैं जिसके लिए खास निगरानी भी रखी जाती हैं। किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सख्ती की जाती हैं। यहाँ तक कि गलत देखने, सुनने एवम बोलने तक कि मनायीं की जाती हैं। शराब एवम अन्य किसी नशे की मनाई रहती हैं।

रमजान के दिनों में किसी भी तरह की लड़ाई को गलत माना जाता हैं। हाथ पैर का गलत इस्तेमाल रमजान के नियमों का उलंघन हैं। यहाँ तक की किसी लड़ाई को देखना भी गलत समझा जाता हैं।

## नेकी का रास्ता दिखाया जाता है

रमजान में दान का महत्व हैं जिसे जकात कहते हैं। सभी को अपनी श्रद्धा एवम स्थिती अनुसार नेक कार्य करना होता हैं। रोजाना किये जाने वाले नेक कार्यों को बढ़ाने को कहा जाता हैं। रमजान में लोगो को उनके गुनाह मानने को कहा जाता हैं जिससे वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सके। जिससे उसके दिल का भार कम होता हैं अगर वो अपनी गलती की तौबा करता हैं तो उसे उसका अहसास होता हैं और वो आगे से ऐसा नही करता।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

M DDOCK





# ये है सबसे 'विवादास्पद फिल्म'!

**आज सोशल मीडिया से लेकर किसी भी राजनैतिक पार्टी को ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कलाकारों ने फिर से यहां काम करना शुरू कर दिया है. अब उनपर कोई रोक टोक नहीं है.**

**शुभम गुप्ता**

पिछले साल उरी में सेना के कैंप पर पाकिस्तानी हमले के बाद देश में जबर्दस्त उबाल था. कुछ लोगों ने यह मुद्दा ही बना लिया था कि जो देश आतंकी हमले करवाता है, वहां के कलाकारों को देश में काम नहीं करने दिया जाए. आखिर फिल्म 'ए दिल है मुश्किल' को लेकर करण जौहर को जिस तरह से टारगेट किया गया. उसमें पाकिस्तानी हीरो फवाद खान थे. आखिर करण जौहर को यह वचन देना पड़ा था कि वे पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे. उसके बाद नंबर आया शाहरुख खान का. उनकी फिल्म रईस में पाकिस्तानी हिरोइन मायरा खान जो थीं. लेकिन शाहरुख ने समय रहते महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के घर समर्पण कर दिया. और रईस 'निर्विघ्न' रिलीज हो गई.

देश के हर न्यूज चैनल पर इसे लेकर खूब बहस हुई. उसके बाद से ये भी कहा गया कि अब कोई भी बॉलीवुड का डायरेक्टर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेगा. मगर ये क्या.. आप टीवी पर रोजाना एक फिल्म का ट्रेलर देख रहे होंगे, इस फिल्म का नाम है हिंदी मीडियम. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं इरफान खान और साथ में हीरोइन हैं सबा कमर.

सबा कमर पाकिस्तानी कलाकार हैं. कई पाकिस्तानी सीरियलों में काम कर चुकी हैं. मगर हिंदुस्तान में उनकी ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है. उस समय उरी हमले में हमारे जवान शहीद हुए थे, तो क्या अभी जवान शहीद नहीं हो रहे है? क्या अब किसी को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कलाकार कैसे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं. यहां तक कि पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने इसी फिल्म में गाना भी गाया है.

इन सब चीजों से साफ नजर आता है कि ये सिर्फ करण जौहर और शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए किया गया था. वरना जवान तो आज भी शहीद हो रहे हैं. मगर आज सब फिल्म के ट्रेलर को इन्जॉय कर रहे हैं. हर कोई अब इस नई हीरोइन सबा कमर की तारीफों के पुल बांध रहा है. आतिफ के गाने के मजे लिए जा रहे हैं. वैसे ये बता दें कि यही सबा कमर पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बॉलीवुड के कई हीरो की खिल्ली उड़ा रही थीं. (देखें वीडियो)

लेकिन आज सोशल मीडिया से लेकर किसी भी राजनैतिक पार्टी को ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कलाकारों ने फिर से यहां काम करना शुरू कर दिया है. अब उनपर कोई रोक टोक नहीं है. रोक-टोक सिर्फ करण और शाहरुख खान के लिए ही होती है.

आप सभी को ये बात अब समझ जानी चाहिए कि ये सब देशभक्ति के नाम पर नाटक होता है. उस समय सोशल मीडिया पर ये मैसेज आया कि फवाद खान हिंदुस्तान से पैसा कमाकर पाकिस्तान ले जाएगा और वहां की सरकार को टैक्स देगा और पाकिस्तानी सरकार उस पैसे से आर्मी के लिए गोली खरीदेगी. और वो गोली लगेगी हिंदुस्तानी सैनिकों को. तो अब सबा पैसा कमा कर नहीं ले जाएगी, क्या अब गोली नहीं लगेगी?

अब कम से कम आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि ये सब फिक्स डील होती है. एक फिल्म की पटकथा की तरह सबकुछ पहले से तय होता है. यहां हीरो न तो हीरो है, और विलेन भी विलेन नहीं है.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# ऐसा कानून जो महिलाओं का शोषण करता है

21वीं सदी में सेक्सिस्ट कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है और ये बात दुनिया को जानने और समझने की जरुरत है. देर होने से पहले सभी को ये बात समझ आ जाए तो ठीक नहीं तो अंत तो सभी का होना है.

## क्या

आप जानते हैं कि कुछ देशों में किसी महिला का अपहरण करने के बाद उससे शादी कर लेना कानूनी तौर पर जायज है? जी, ये कोई भद्दा मजाक नहीं, बल्कि कड़वा सच है!

एक ओर जहां महिलाएं समाज में समान अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रही हैं तो दूसरी ओर दुनिया में अभी भी ऐसे कई देश हैं जहां के कानून उनको समानता का अधिकार तो दूर की बात जीने के अधिकार के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी कठिन बनाते हैं. रूस में महिलाओं को ट्रेन या ट्रैक्टर चलाने पर पाबंदी है तो भारत में मैराइटल रेप जैसी वहशियत को कानूनी दर्जा मिलने जैसे सेक्सिस्ट कानून पूरे विश्व में पाए जाते हैं.

आइए आपको बताते पाँच ऐसे देशों की लिस्ट जिन्हें शायद ये अहसास ही नहीं है कि अब 21वीं सदी आ चुकी है.

जॉर्डन, लेबनान, और मोनाको जैसे देशों में महिलाओं को नागरिकता के नाम पर सेकेंड क्लास सीटिजन का दर्जा मिलता है

अभी भी ऐसे देश हैं जहां महिलाओं के खिलाफ भेदभाव में कोई कोताही नहीं की जाती. इन देशों में जब एक नागरिक के बतौर महिलाओं के पहचान की बात आती है तो उन्हें दोयम दर्जा ही दिया जाता है. उदाहरण के तौर पर जॉर्डन और लेबनान में किसी बच्चे की नागरिकता उसके पिता से ही तय होता है. मतलब अगर बच्चे को जॉर्डन या लेबनान की नागरिकता चाहिए तो पिता जॉर्डन या लेबनान का नागरिक होना चाहिए. मां की राष्ट्रीयता क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता!

हालांकि महिलाओं की दुर्दशा में लेबनान एक कदम आगे ही है. यहां के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी औरत का रेप या अपहरण करता है और वो पीड़िता से शादी कर लेता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

नाइजीरिया में एक पति अपनी पत्नी को तब तक मार सकता है जब तक कि उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं लग जाती.

### मारो लेकिन दाग ना दिखे

घरेलू हिंसा. ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे दुनिया का कोई भी देश या समाज अनछुआ नहीं है. असल में दुनिया में 46 ऐसे देश हैं जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से किसी भी तरह का कोई कानूनी संरक्षण नहीं देते हैं. हालांकि नाइजीरिया में पुरुषों अपनी विवाहिता पत्नियों को मारने की कानूनी अनुमति नहीं है.

नाइजीरिया के कानून के मुताबिक पति अपनी पत्नी को 'सुधारने के उद्देश्य से' मार सकता है. हालांकि नाइजीरिया वाले महिलाओं के प्रति इतने भी क्रूर नहीं हैं. उन्होंने पति की कुटाई पर ये शर्त जरुर लगा दी है कि वो बीवी को मार तो सकता है लेकिन उसके शरीर पर मार के या घाव के गहरे निशान नहीं पड़ने चाहिए. अब आखिर यार पत्नी की सुरक्षा के नाम पर उसे इतना हक देना तो बनता है ना? बेशर्म समाज और बेशर्म लोग.

चिली और ट्यूनीशिया जैसे देशों में पुरुष को खानदानी संपत्ति में ज्यादा हिस्सा दिया जाता है

जब बात संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो लड़की हो या लड़का हिस्सा बराबरी में बंटना चाहिए

ना? लेकिन ट्यूनीशिया के लोगों को ऐसा नहीं लगता. वहां के 1956 में बने कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि- 'जिस भी घर में बेटा है, वहां की संपत्ति में पुरूष को महिला से दो गुना हिस्सा दिया जाएगा.'

कुछ देशों के लिए सहमति नाम का शब्द अभी भी एक किसी दूसरे ग्रह का विषय है. क्योंकि वहां 'नहीं' का अर्थ 'नहीं' होता है. सिंगापुर और भारत में मैराइटल रेप यानि साथी की सहमति के बिना किया गया सेक्स किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. और ना ही इसे रेप माना जाता है.

यमन एक ऐसा देश है जहां अभी भी बाल विवाह काफी बड़े पैमाने पर होता है. यहां शादी में रेप को परिभाषित करने की कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं है.

### महिला अधिकार

दुनिया में लिंग भेद का कोई प्रतिनिधि देश है तो वो है सऊदी अरब. ये देश आज भी 1990 में लगाए गए एक फतवे को फॉलो कर रहा है. इसके अनुसार महिलाओं को कार चलाने की मनाही है.

कई बहादुर महिलाओं द्वारा इस फतवे के विरोध किए जाने और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ लगतार अभियान चलाए जाने के बावजूद सऊदी अरब इस फैसले को बदलने को राजी नहीं हो. और सबसे मजेदार बात ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस खाड़ी देश को अपने महिला अधिकार आयोग में चुना है. वो भी एक-दो नहीं बल्कि चार साल के कार्यकाल के लिए. जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं!

महिलाओं को अगर बराबरी का स्थान देना है तो इस तरह की संस्थागत असमानता को पहले खत्म करना होगा. 21वीं सदी में सेक्सिस्ट कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है और ये बात दुनिया को जानने और समझने की जरुरत है.

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of

गुड हैबीट

# हमेशा पढ़ना हर उम्र में जरूरी है

**अकसर** लोग या तो शौक से या किसी मकसद से कोई पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि वास्तव में पढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। अगर आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसे शौक के तौर पर शुरू करना चाहिए। हर दिन एक किताब के कुछ पन्ने पढ़ने की धीरे-धीरे आदत डालें। जल्द ही आपको पढ़ने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप मूवी की बजाए किताब पढ़ने को तरजीह देंगे।

## दिमाग का अभ्यास

पढ़ने में आपके दिमाग का अभ्यास होता है। पढ़ने के दौरान आपका दिमाग जितना उत्तेजित होता है, उतना टी.वी. देखने या रेडियो सुनते वक्त नहीं होता है। और जाहिर सी बात है जब दिमाग का अभ्यास होगा तो दिमाग स्वस्थ भी रहेगा।

## तनाव कम होता है

तनाव के स्तर को कम करने के लिए पढ़ने एक असरदार तरीका है क्योंकि एक अच्छी स्टोरी में आप खो जाते हैं और आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। इससे तनाव कम होता है।

## बेहतर नींद में मदद

पढ़ने से आप रिलैक्स फील करते हैं इससे सही नींद आती है। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स की कृत्रिम लाइट आपके दिमाग को संकेत देती है कि अभी जागने का समय है इसलिए जब आपको सोना हो तो उससे एक घंटे पहले टेलीविजन, सेल फोन या लैपटॉप से परहेज करें और एक किताब उठाकर करीब एक घंटे पढ़ें।

## याददाश्त मजबूत होती है

जब आप फिक्शन पढ़ते हैं तो आपका दिमाग कहानी के सभी कैरक्टर, सारी घटनाओं और कहानी के प्लॉट को याद रखता है। यानी रोजाना पढ़ने का मतलब अपनी याददाश्त का अभ्यास कराना है और अभ्यास से चीजें मजबूत होती हैं। इसलिए रोजाना पढ़ने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है।

## शांत और संयमित करता है

आपको रिलैक्स फील होने के अलावा पढ़ने से आपके अंदर एक तरह की शांति और सुकून का भाव पैदा होता है। स्टडीज में यह बात सामने आई है कि आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तक पढ़ने से ब्लड प्रेशर कम होता है जिससे आप शांत होते हैं।

## एकाग्रता बढ़ती है

पढ़ने से आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान एक ही तरफ केंद्रित होता है। आज के जमाने में हमारा दिमाग कई कामों में बंटा होता है, हमें अपना काम करना होता है तो अपने फोन भी चेक करने पड़ते हैं, लोगों से बात करनी पड़ती है। इससे हमारा एकाग्रता स्तर कम होता है और प्रॉडक्टिविटी में गिरावट आती है। हर दिन थोड़े समय तक पढ़ने से इस तरह की चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है।



## प्रेरणा का स्रोत

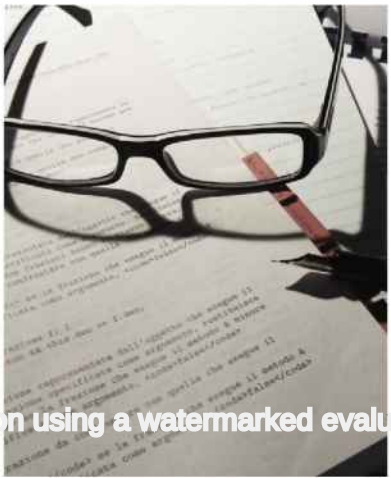

इंग्लैंड में की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि 60 फीसदी प्रतिभागियों का मानना था कि पढ़ने से उनके जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रभाव पड़ा है। पढ़ने के दौरान आप कैरक्टर के इमोशन को महसूस करते हैं। इससे आपके अंदर बड़ा बदलाव आता है।

## शब्द भंडार बढ़ता है

पढ़ने से ज्ञान के साथ-साथ शब्द भंडार भी बढ़ती है। पढ़ने के दौरान आपके सामने कई शब्द आते हैं जो आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और खुद से आपकी स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं। शब्दों का सही भंडार होने से आपनी बात स्पष्ट ढंग से रखने की कला आप में विकसित होती है जो आपके पेशे के लिए फायदेमंद होगा।

## विश्लेषण क्षमता में इजाफा

जब आप किताब पढ़ते हैं तो अकसर यह महसूस कर लेते हैं कि अंत में क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेखक आपके लिए कई क्लू छोड़ देता है जिसे आपका दिमाग एक साथ जोड़ता है और दिमाग में कहानी के अंत की तस्वीर उभरती है। इस प्रक्रिया से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और ऐनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है। इन स्किल्स का इस्तेमाल जीवन के अन्य मैदान में किया जा सकता है और साथ ही अपने परफॉर्मेंस में सुधार के लिए भी इसका इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# विश्व का सबसे ऊँचा पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है?

विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर बनाया जायेगा. चिनाब नदी पर बनाए जाने वाले रेल पुल की ऊंचाई एफिल टॉवर से 35 मीटर ज्यादा होंगी. इस पुल के निर्माण के बाद बारामूला से जम्मू का रास्ता साढ़े घंटे में तय किया जा सकेगा, जबकि बारामूला से जम्मू की दूरी तय करने के लिए सड़क मार्ग से 13 घंटे लगते है।

**हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ?**

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खडगे को नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खडगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भारतीय राजनीतिज्ञ है। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खडगे लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता है।

**किस राज्य द्वारा वितीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर स्थानांतरित किया गया है ?**

मध्यप्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर स्थानांतरित किया गया है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है क्योकि भारत में 1867 में अप्रैल-मार्च को वित्तीय वर्ष अपनाया गया था। अब मध्यप्रदेश में अगला वित्तीय वर्ष का बजट सत्र दिसम्बर 2017 से या फिर जनवरी 2018 में पेश किया जायेगा।

**हाल ही में पहली बार किस क्रूज पर रेसिंग ट्रैक बनाया गया है ?**

जर्मनी के पेपनबर्ग स्थित मेयर वेफ्ट शिपयार्ड में 3,840 यात्रियों की क्षमता वाले नॉर्वेजियन क्रूज लाइन सुपर लग्जरी जहाज में रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यह पहला रेसिंग ट्रैक है, जो क्रूज पर बनाया गया है यह ट्रैक 333 मीटर लंबा है। इस ट्रैक पर एक साथ 10 ड्राइवर थ्रिल ड्राइव कर सकते है। इसमें एक ओपन शॉपिंग सेंटर भी खोला गया है, जिसमे ड्यूटी फ्री सामान खरीदा जा सकता है।

**लोक लेखा समिति क्या है ?**

लोक लेखा समिति भारतीय संसद के चुने हुए सदस्यों वाली समिति है, जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परिक्षण करती है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गए लेखा परिक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है यह समिति संसद द्वारा निर्मित है।

**ट्रांसफॉरमेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ?**

ट्रांसफॉरमेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया है। नायडू को यह पुरस्कार राज्य स्तर पर अमेरिका और भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है।

**हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ?**

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कसिनाधुनी विश्वनाथ को सम्मानित किया गया है। कसिनाधुनी विश्वनाथ को यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। कसिनाधुनी विश्वनाथ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 48वें व्यक्ति है कसिनाधुनी विश्वनाथको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

**ब्रह्मोस ब्लॉक-3 क्या है ?**

ब्रह्मोस ब्लॉक-3 रूस और भारत की एक संयुक्त परियोजना है, जो रूस के पी-800 ओनिक्स मिसाइल पर आधारित है। हाल ही में जमीन पर मार करने वाली इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सफल परिक्षण किया गया है।

**विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है ?**

विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है यह दिवस पकडे जाने और खाए जाने वाली विश्व की सबसे लोकप्रिय मच्छलियों को बचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह खारे पानी की मछली है, जो की मैकेरल परिवार के एक उप-समूह जनजाति थ्युननिनी के अंतर्गत आती है।

**ब्रिटेन के शिप शेफील्ड को कब डुबोया गया था ?**

ब्रिटेन के शिप शेफील्ड को 3 मई 1982 को अर्जेंटीना ने मिसाइल से हमला कर डुबो दिया थो अर्जेंटीना द्वारा किये गए इस हमले में 20 लोग मारे गए थे, तथा 24 घायल हो गए थे। इस हमले के समय जहाज में 268 लोग मौजूद थे। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच जमीनी लड़ाई हुई थी, जिसमे अर्जेंटीना को ब्रिटेन के सामने घुटने टेकने पड़े थे।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

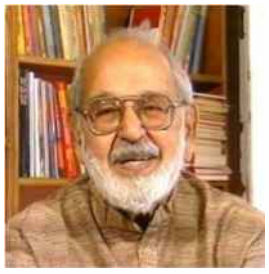

## सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन "अज्ञेय"

जन्म 07 मार्च 1911 – निधन 04 अप्रैल 1987
जन्म स्थान – कुशीनगर, देवरिया, उत्तरप्रदेश
कुछ प्रमुख कृतियाँ : हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इन्द्र-धनु रौंदे हुए थे , आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार
विविध : कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिये 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। आँगन के पार द्वार के लिये 1964 का साहित्य अकादमी पुरस्कार

आओ बैठें
इसी ढाल की हरी घास पर।

माली-चौकीदारों का यह समय नहीं है,
और घास तो अधुनातन मानव-मन की भावना की तरह
सदा बिछी है-हरी, न्यौती, कोई आ कर रौंदे।

आओ, बैठो
तनिक और सट कर, कि हमारे बीच स्नेह-भर का व्यवधान रहे,
बस,
नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की।

चाहे बोलो, चाहे धीरे-धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ,
चाहे चुप रह जाओ-
हो प्रकृतस्थ : तनो मत कटी-छँटी उस बाड़ सरीखी,
नमो, खुल खिलो, सहज मिलो
अन्त:स्मित, अन्त:संयत हरी घास-सी।

क्षण-भर भुला सकें हम
नगरी की बेचैन बुदकती गड्ड-मड्ड अकुलाहट-
और न मानें उसे पलायन;
क्षण-भर देख सकें आकाश, धरा, दूर्वा, मेघाली,
पौधे, लता दोलती, फूल, झरे पत्ते, तितली-भुनगे,
फुनगी पर पूँछ उठा कर इतराती छोटी-सी चिड़िया-
और न सहसा चोर कह उठे मन में-
प्रकृतिवाद है स्खलन
क्योंकि युग जनवादी है।

क्षण-भर हम न रहें रह कर भी :
सुनें गूँज भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की
जिस की छाती की हम दोनों छोटी-सी सिहरन हैं-
जैसे सीपी सदा सुना करती है।

क्षण-भर लय हों-मैं भी, तुम भी,
और न सिमटें सोच कि हम ने
अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना!

क्षण-भर अनायास हम याद करें :
तिरती नाव नदी में,
धूल-भरे पथ पर असाढ़ की भभक, झील में साथ तैरना,
हँसी अकारण खड़े महा वट की छाया में,
वदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलक-लट,
चीड़ों का वन, साथ-साथ दुलकी चलते दो घोड़े,
गीली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्रायी सीटी स्टीमर की,
खँडहर, ग्रथित अँगुलियाँ, बाँसे का मधु,
डाकिये के पैरों की चाप,
अधजानी बबूल की धूल मिली-सी गन्ध,
झरा रेशम शिरीष का, कविता के पद,
मसजिद के गुम्बद के पीछे सूर्य डूबता धीरे-धीरे,
झरने के चमकीले पत्थर, मोर-मोरनी, घुँघरू,
सन्थाली झूमुर का लम्बा कसक-भरा आलाप,
रेल का आह की तरह धीरे-धीरे खिंचना, लहरें
आँधी-पानी,
नदी किनारे की रेती पर बित्ते-भर की छाँह झाड़ की
अंगुल-अंगुल नाप-नाप कर तोड़े तिनकों का समूह,
लू,
मौन।

याद कर सकें अनायास : और न मानें
हम अतीत के शरणार्थी हैं;
स्मरण हमारा-जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन-
हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप-बोध से।
आओ बैठो : क्षण-भर :
यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर-सेठों की फैयाजी से।
हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा।

आओ बैठो : क्षण-भर तुम्हें निहारूँ
अपनी जानी एक-एक रेखा पहचानूँ
चेहरे की, आँखों की-अन्तर्मन की
और-हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की :
तुम्हें निहारूँ,
झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है!

धीरे-धीरे
धुँधले में चेहरे की रेखाएँ मिट जाएँ-
केवल नेत्र जगें : उतनी ही धीरे
हरी घास की पत्ती-पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में
और झाड़ियाँ भी घुल जावें क्षिति-रेखा के मसृण ध्वान्त में;
केवल बना रहे विस्तार-हमारा बोध
मुक्ति का,
सीमाहीन खुलेपन का ही।

चलो, उठें अब,
अब तक हम थे बन्धु सैर को आये-
(देखे हैं क्या कभी घास पर लोट-पोट होते सतभैये शोर मचाते?)
और रहे बैठे तो लोग कहेंगे
धुँधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं।

-वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने :
(जिस के खुले निमन्त्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है
और वह नहीं बोली),
नहीं सुनें हम वह नगरी के नागरिकों से
जिन की भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की
किन्तु नहीं है करुणा।

उठो, चलें, प्रिय!

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

रुल्स

# टैटू... इतना आसान नहीं है

**वो दिन गए जब केवल रॉकस्टार्स और बाइकर्स टैटू बनवाते थे। अब तो टैटू सामान्य से सामान्य इंसान के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपके मन में भी टैटू बनवाने का आइडिया आया है तो मन मसोसकर ही न रह जाएं बल्कि बनवा ही डालिए टैटू लेकिन जरा इन बातों का खास ध्यान भी रखें।**

टैटू बनवाने का सबसे बड़ा रूल तो यही है कि सस्ते के चक्कर में न पड़ें क्योंकि सस्ता टैटू आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर आपने टैटू बनवाने का मन बना ही लिया है तो सस्ते और अनहाइजिनिक जगह पर भूलकर भी न जाएं।

इस बात का ध्यान रखें कि टैटू बनाने के लिए नई सुईयों का इस्तेमाल हो क्योंकि पुरानी सुईयों से कई गंभीर रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे टीटनेस, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारियां तो हो ही सकती हैं इसके अलावा इससे एड्स जैसा गंभीर रोग भी हो सकता है। इसके अलावा टैटू कलर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।

टैटू करवाने से पहले शराब पीकर न जाएं। शराब

आपके खून को पतला कर देता है जिससे टैटू करवाने के दौरान ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकता हैं। इससे त्वचा पर घाव जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं।

टैटू करवाने के बाद त्वचा की उचित देखभाल की भी जरुरत होती है। इस दौरान त्वचा की देखभाल न करने से इंफेक्शन हो सकता है जो आपके लिए जिंदगीभर की मुसीबत बन सकता है। टैटू बनवाने के बाद त्वचा के नॉर्मल होने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। टैटू के बाद त्वचा को खुजलाने से बचें। अगर आप जिम जाते हैं तो भी इस बात का खास ख्याल रखें कि टैटू वाले जगह पर गलती से भी कोई चोट न लगे।

लेकिन टैटू बनवाने के साइड इफेक्ट्स आपको जिंदगीभर झेलने पड़ सकते हैं। जीवन में कभी भी टफ्क करवाने के दौरान आपको त्वचा में जलन और दर्द की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टैटू बनाने में जिस इंक का इस्तेमाल होता है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। टफ्कमशीन में ये गर्म होने लगता है। इसके अलावा सूर्य की किरणों से भी उस जगह का बचाव करना जरूरी हो जाता है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# रिवाजों में छुपे वैज्ञानिक रहस्य

भारतीय शादियों में होने वाली रस्मों को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद माना जाता है। शादी में मेंहदी लगाने से लेकर फेरों तक का अपना अलग-अलग महत्व होता हैं।

## शादियों में होने वाली रस्में

भारतीय शादियों में कई तरह-तरह की रस्में निभाई जाती हैं, ये परंपरायें बहुत पुरानी भी हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं लेकिन इन रस्मों के पीछे कई वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हैं। भारतीय शादियों में होने वाली रस्मों को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद माना जाता है। शादी में मेंहदी लगाने से लेकर फेरों तक के अपने-अपने महत्व हैं। आप भी जानिये भारतीय शादियों में होने वाली इन रस्मों के बारे में।

## हाथों में मेंहदी लगाना

शादी से पहले लड़की के हाथों में मेंहदी लगाई जाती है। मेहंदी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। मेंहदी में ठंडक प्रदान करने का गुण होता है जो वर वधू को तनाव, सिरदर्द और बुखार जैसी समस्याओं से आराम दिलाता है। इसके अलावा मेंहदी कई प्रकार क वायरल और फंगल संक्रमण से बचाता भी है।

## हल्दी लगाने की परंपरा

हल्दी ऐसा मसाला है जिसमें कई तरह के गुण होते हैं। शादी से पहले वधू के चेहरे पर हल्दी लगाने की रस्मे होती है, इससे चेहरे पर निखार आता है। इस दौरान हल्दी का लेप पूरे शरीर पर भी लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने भी हल्दी को चमत्कारिक जडी-बूटी कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। हल्दी त्वचा के बैकटीरिया को नष्ट कर त्वचा में निखार लाता है।

## चूड़ियां पहनना

शादी के वक्त वधू के दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाई जाती हैं। कलाईयों में कई एक्युप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, चूड़ी पहनने पर इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है जो आपको स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसके साथ चूड़ियों और त्वचा के बीच होने वाला घर्षण रक्त संचार सुचारु करता है।

## मांग में सिन्दूर भरना

हिंदू रीति-रिवाजों में महिलाओं के मांग में सिन्दूर का बड़ा महत्व है। यह स्त्री के शादी-शुदा होने की निशानी है। इसके अलावा यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें हल्दी, चूना, कुछ धातु और पारा होता है। जब वधू की मांग में सिन्दूर भरा जाता है तो पारा शरीर को ठंडक प्रदान करता है तथा शरीर को आराम महसूस होता है।

## बिछुए पहनना

हिंदू धर्म में शादी के दौरान वधू के पैरों में बिछुए पहनाये जाते हैं। इसके भी कई वैज्ञानिक कारण हैं। पैर की दूसरी उंगली में एक विशेष नस होती है जो गर्भाशय से गुजरती है तथा हृदय तक जाती है। बिछुए गर्भाशय को मजबूत बनाते हैं तथा मासिक धर्म को नियमित करते हैं। बिछुए चांदी के बने होते हैं जो ध्रुवीय उर्जा को पृथ्वी से शरीर में स्थानांतरित करती हैं।

## अग्नि के फेरे लेना

अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसके चारों तरफ फेरे लेकर वर-वधू एक-दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं।

दरअसल आग आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, यह नकारात्मक उर्जा को दूर कर सकारात्मकता फैलाती है। इसके साथ जब अग्नि में विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, घी, चावल, के साथ दूसरी वस्तुएं डाली जाती हैं तब आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे आसपास मौजूद लोगों खासकर वर-वधू पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# कटघरे में जेंटलमैन

**हाल ही में सार्वजनिक हुए बीसीसीआई के नये संविधान के दो नियम राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को कठघरे में खड़ा करते हैं...**

## सुप्रीम कोर्ट

द्वारा गठित की गई प्रशासकों की समिति ने बीते मार्च में बीसीसीआई के नए संविधान को हरी झंडी दिखा दी. लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया यह संविधान 18 मार्च से बीसीसीआई की वेबसाईट पर सभी के लिए उपलब्ध है. इसका मकसद देश में क्रिकेट के प्रशासन को दोषमुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. अगर, इस नए संविधान पर गौर करें तो इसमें सबसे ज्यादा जोर ह्यहितों के टकरावह्न से संबंधित मामलों को सुलझाने पर दिया गया है. इसमें हितों के टकराव को खत्म करने के लिए बनाए गए नियमों में दो ऐसे नियम भी हैं, जो सीधे-सीधे भारतीय टीम के दो पूर्व कप्तानों राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को कठघरे में खड़ा करते हैं.

इसमें रोल कम्प्रोमाइज के अनुच्छेद एक में कहा गया है, यदि ए किसी राष्ट्रीय टीम का कोच है और साथ ही वह आईपीएल में भी किसी टीम का कोच है या उससे जुड़ा है तो इस स्थिति में सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला बनता है. इस स्थिति में ए को किसी एक टीम को ही चुनना होगा. माना जा रहा है कि यह नियम विशेष तौर पर राहुल द्रविड़ को देखते हुए बनाया गया है. द्रविड़ इस वक्त भारतीय ए और अंडर-19 टीम के कोच हैं साथ ही वे आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम के मेंटर भी हैं.

ए९सा ही एक और नियम है जो सीधे तौर पर सौरव गांगुली को लेकर हो रहे हितों के टकराव को रोकने के लिए बनाया गया है. गांगुली वर्तमान में

PDF compression, OCR, web-optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं और उनके आईपीएल की राइजिंग पुणे सुपर ज्वाइंट टीम के मालिक के साथ व्यवसायिक संबंध भी हैं. दरअसल, पुणे की टीम के मालिक संजीव गोयनका इंडियन सुपर लीग में एटलेटिको डि कोलकाता टीम के भी मालिक हैं. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एटलेटिको डि कोलकाता टीम के सह मालिक हैं. बीसीसीआई के नए संविधान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित नामक कॉलम में कहा गया है, यदि सी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का सदस्य है और उसके आईपीएल की किसी भी टीम के मालिक के साथ व्यवसायिक संबंध हैं तो ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से हितों के टकराव का मामला बनता है.

## इस्तीफा न देने का कारण

जेंटलमैन्स गेम कहलाने वाले क्रिकेट में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली उन खिलाड़ियों की सूची में हमेशा पहले स्थान पर आते हैं जो इस परिभाषा पर खरे उतरते हैं. कई बार देखा गया कि अंपायर के अंगुली उठाने से पहले ही द्रविड़ पैवेलियन की ओर चल पड़ते थे. खेल के अलावा भी भारतीय टीम के इस पूर्व कप्तान ने पिछले सालों में देश के सामने एक नजीर पेश की थी. जिसके लिए वे काफी सुर्खियों में भी रहे थे. उन्होंने बेंगलुरु विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि लेने से यह कहते हुए इनकार दिया था कि वे खेल के क्षेत्र में रिसर्च करके अपनी मेहनत से इस डिग्री को हासिल करेंगे. लेकिन, ईमानदारी और नैतिकता की ऐसी मिसालें पेश करने वाले द्रविड़ आखिर क्यों हितों के टकराव के बाद भी दोनों पदों पर बने हुए हैं यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता है.

कुछ जानकार इसके पीछे की मुख्य वजह बीसीसीआई और राहुल द्रविड़ के बीच हुए अनुबंध को मानते हैं. ये लोग बताते हैं कि बीसीसीआई ने जब द्रविड़ को ए टीम का कोच बनाने का फैसला किया तो उन्होंने आईपीएल से भी जुड़े रहने की शर्त रख दी थी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि उन्हें आईपीएल में किसी टीम से न जुड़ने दिया जाए तो इसके लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाए. बताया जाता है कि बीसीसीआई ने इस मामले पर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए बीच का रास्ता निकाला. उसने द्रविड़ और ऐसे ही मामलों वाले अन्य लोगों के साथ 10 महीने का अनुबंध करने का फैसला किया जिससे कि ये लोग साल के बाकी दो महीनों में आईपीएल की किसी टीम से जुड़ सकें.

हितों के टकराव के बावजूद सौरव गांगुली के इस्तीफा न देने के कारण को भी जानकार सही नहीं मानते. उनके मुताबिक ह्यराइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्सह्ल की टीम को आईपीएल में केवल दो साल ही रहना है और यह साल यानी 2017 आईपीएल में उसका आखिरी साल होगा. ऐसे में गांगुली सोच रहे हैं कि एक महीने बाद जब यह टीम आईपीएल से बाहर हो जाएगी तो हितों का टकराव अपने आप खत्म हो जाएगा.

## क्यों सवाल उठाना जायज है

क्रिकेट के कुछ पत्रकार 10 महीने के अनुबंध को सही नहीं मानते. उनका कहना है कि बीसीसीआई ने किसी तरह के कानूनी विवाद से बचने के लिए द्रविड़ और राष्ट्रीय टीम में सेवाएं दे रहे अन्य लोगों के लिए यह बीच का रास्ता निकाला है जो नैतिक रूप से बिलकुल गलत है. जानकारों के मुताबिक जब इन दिग्गजों को पता है कि दो महीने आईपीएल खेलने के बाद उन्हें फिर राष्ट्रीय टीम से ही जुड़ना है तो नैतिक रूप से हितों के टकराव का मामला तो बनता ही है. कई मानते हैं कि राहुल द्रविड़ जैसे व्यक्ति से तो इसकी अपेक्षा बिलकुल नहीं की जा सकती.

हालांकि, बीसीसीआई से जुड़े कुछ अधिकारी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासनिक समिति भी मानती है कि 10 महीने का अनुबंध गलत है और इससे हितों के टकराव का मामला बनता है. इसीलिए उन्होंने यह भी तय किया कि आगे से 10 का नहीं बल्कि पूरे 12 महीने का अनुबंध होगा जिससे राष्ट्रीय टीमों से जुड़े लोग आईपीएल से दूर रखे जा सकें. हालांकि, उन्हें कोई नुकसान न हो, इसके लिए उनके वेतन में बढ़ोतरी भी की जाएगी.

## द्रविड़ के कारण ही हुआ

क्रिकेट की एक अंग्रेजी पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक समिति द्वारा अचानक बीसीसीआई के नए संविधान को हरी झंडी दिखाया जाना और उसे तेजी से बेवसाइट पर अपलोड किए जाने के पीछे का कारण भी राहुल द्रविड़ ही हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की टीम को यह मामला गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया.

इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-फरवरी में भारत अंडर-19 और इंग्लैण्ड अंडर-19 की टीमों के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज मुंबई में खेली गई थी. बताया जाता है कि इस सीरीज के बीच में राहुल द्रविड़ ने पांच खिलाड़ियों को सीरीज से हटने की इजाजत दे दी. उन्होंने ऐसा तब किया जब भारतीय टीम को एक मैच खेलना बाकी था. पत्रिका के मुताबिक इन पांच में से तीन खिलाड़ियों ने अगले दिन दिल्ली आकर आईपीएल की टीम दिल्ली डेयर डेविल्स (जिसके द्रविड़ मेंटर है) में चयन के लिए ट्रायल दिया था. इस घटना के बाद सवाल उठे कि क्या द्रविड़ ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए इन खिलाड़ियों को ट्रायल देने के लिए सीरीज से हटने की इजाजत दी थी. बताया जाता है कि जब यह खबर प्रशासकों की समिति तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए संविधान को जल्द तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# तो बच जाएंगे होने वाली दुर्घटनाओं से

थोड़ा सा दूध आपकी सभी परेशानियों को दूर सकता है। चौंकिए मत, क्योंकि ऐसा सम्भव है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है और दूध में आपकी परेशानियों को कम करने की शक्ति भी होती है।

- अगर आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही है तो शुक्ल पक्ष अमावस्या के तुरंत बाद मंगलवार को 400 ग्राम दूध में चावल धोकर नदी में बहा दें। ऐसा लगातार सात मंगलवार करें। इसके बाद आपको खुद ही फर्क नजर आने लगेगा।
- अगर आप आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं तो रात में एक गिलास दूध अपने सिर के पास रखकर सो जाएं और सुबह उसी दूध को बबूल के पेड़ में डाल दें।
- कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा अच्छी नहीं होने पर लगातार सात सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
- घर में मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इसके लिए आपको दूध में चीनी और घी को मिलाकर पीपल के पेड़ के जड़ में डालना होगा।
- कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ होने पर दूध में चीनी और केसर मिलाकर शाम को शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से गुरु मजबूत होगा।

# कष्टदायक जीवन से मुक्ति के लिए हैं उपाय

कुंडली में शनि की दशा बिगड़ने पर व्यक्ति की जिंदगी में बुरे दौर की शुरूआत हो जाती है। उस समय किए जा रहे सभी शुभ कार्य का परिणाम उलटा होता है। व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालता है, उससे नुकसान ही पहुंचता है और चाहकर भी शनि का प्रभाव कम नहीं कर पाता। अगर आपकी कुंडली में भी शनि हावी चल रहा है तो ये उपाय आपको शनि की पीड़ा से मुक्त करवाएंगे।

- शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर पूजा करें और सूर्यादय से पहले ही एक घंटे तक भगवान हनुमान की तस्वीर के सामने बैठकर
- 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंगबली को चूरमे और लड्डू का भोग लगाएं।
- काली गाय की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते है। काली गाय के सिर पर रोली लगाकर सींगों में कलावा बांधें और धूप आरती करें। इसके बार परिक्रमा करके गाय को बूंदी के चार लड्डू खिलाएं।
- पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दीपक जलाएं।
- अनष्टि शनि लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति के मकान का दरवाजा पश्चिम दिशा में रहता है। ऐसे व्यक्ति की उम्र के 36, 42, 45 और 48 वाले वर्ष बहुत ही कष्टदायक होते हैं। ऐसे में सूरमा लाकर उसे जमीन में गाढ़ दें।
- शनिवार को व्रत रखें और सूर्यास्त के बाद बजरंगबली की पूजा करने के बाद व्रत संपन करें। पूजन में सिंदूर, काली तिल्ली का तेल, इसी तेल का दीपक और रक्त वर्णय पुष्प का शामिल करें। ऐसा पांच या सात शनिवार करने से साढ़ेसाती का प्रभाव कम हो जाता है।
- हर शनिवार को सूर्योदय से पहले वट या पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दीपक जलाएं।
- प्रत्येक शनिवार को बंदरों को केला, मीठी, खील, गुड़ और काले चने खिलाने से शनि की

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# बाहर ही नहीं अंदर से भी फिट बनें

जब आप गुस्सा करते हैं या तनाव और अवसाद से ग्रसित होते हैं इसके अलावा जब आप नकारात्मक सोच से घिरे होते हैं तो इसका सबसे बुरा आप पर ही यानी आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण आप दिन प्रतिदिन बीमार होते चले जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि आप अस्पताल का चक्कर लगाने लग जाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नही है क्यों कि सुदर्शन क्रिया के माध्यम से आप अपने वास्तविक रूप में एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, इससे आपकी फिटनेस अंदरूनी रूप से फिट रहेगी। किसी भी तरह की बीमारी आप से कोसों दूर रहेंगे।

## क्या है सुदर्शन क्रिया

सु का अर्थ है अच्छा या सही, दर्शन का अर्थ है साक्षात्कार और क्रिया एक ऐसा अभ्यास है जो शुद्धि प्रदान करता है। सुदर्शन क्रिया शुद्धिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अभ्यास से हमें अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस क्रिया का अभ्यास हमारे शरीर, मन और आत्मा में एक लय और समन्वयता स्थापित करने में सहायता करता है। अतः सुदर्शन क्रिया एक सांस लेने की लयात्मक, शक्तिशाली और स्वास्थ्यवर्धक विधि है।

ये क्रिया 90 प्रतिशत शरीर के विषाक्त पदार्थ और तनावों को दूरकर प्रतिदिन प्राण को उच्च करती है। जो लोग इस क्रिया को प्रतिदिन करते हैं वे उच्च प्रतिरक्षा शक्ति, सहनशक्ति और लगातार बढ़ी हुई ऊर्जा अनुभव करते हैं। इसका नियमित अभ्यास आपकी निरोगता को बढ़ाकर आपको जीवनभर स्वस्थ और प्रसन्न रखता है।

## सुदर्शन क्रिया का रहस्य

जन्म लेते ही हम जो पहला काम करते है वो है श्वास लेना। श्वास में जीवन के अनजाने रहस्य छिपे है। सुदर्शन क्रिया एक सहज लयबद्ध शक्तिशाली तकनीक है जो विशिष्ट प्राकृतिक श्वांस की लयों के प्रयोग से शरीर, मन और भावनाओं को एक ताल में लाती है। यह तकनीक तनाव, थकान और नकारात्मक भाव जैसे क्रोध, निराशा, अवसाद से मुक्त कर शांत व एकाग्र मन, ऊर्जित शरीर, और एक गहरे विश्राम में लाती है।

सुदर्शन क्रिया जीवन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करती है, इसके रहस्यों को उजागर करती है। यह एक अध्यात्मिक खोज है जो हमें अनंत की एक झलक देती है। सुदर्शन क्रिया स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और जीवन से परेके ज्ञान का अनजाना रहस्य है!

## सुदर्शन क्रिया कैसे करें

आपको बता दें कि सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा कराई जाती है, इसके प्रशिक्षण शिविरों में सुदर्शन क्रिया का बेसिक कोर्स कराया जाता है। संस्था के योग गुरू निर्भय सिंह राजपूत के मुताबिक, रोजाना सुबह घर पर सुदर्शन क्रिया का पूरा अभ्यास करने में तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगता है। क्रिया के अंत में शवासन में लेटना होता है। क्रिया कर लेने के बाद मन बेहद शांत हो जाता है। इसका लगातार अभ्यास हमें सिखाता है कि वर्तमान में कैसे रहा जाए। ज्यादा एनर्जेटिक रहने के अलावा, मुश्किल परिस्थितयों से लड़ने की क्षमता जाग्रत होती है। योग गुरू के मुताबिक बिना प्रशिक्षण के इस क्रिया को न करें।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

# आपका

# नेशन अलर्ट

## आप हासिल कर सकते हैं

## 30% छूट के साथ

### हां, मैं नेशन अलर्ट का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूं

| टिक करें | अवधि | कुल अंक | कवर मूल्य (रु.) | आपको देना है (रु) | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5 वर्ष | 60 | 1200 | 840 | 30% |
| ☐ | 4 वर्ष | 48 | 960 | 720 | 25% |
| ☐ | 3 वर्ष | 36 | 720 | 576 | 20% |
| ☐ | 2 वर्ष | 24 | 480 | 408 | 15% |
| ☐ | 1वर्ष | 12 | 240 | 216 | 10% |

अपने पसंद के ऑफर पर निशान लगाएं
और ग्राहकी फार्म भरकर इस पते पर भेजें

**नेशन अलर्ट कार्यालय,**
प्लॉट नं. 29, विकासनगर, लखोली
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ पिन- 491441

चेक/डीडी से भुगतान

मैं "नेशन अलर्ट" के पक्ष में भेज रहा/रही हूं ..... दिनांक : ..... आहरित बैंक (बैंक का नाम).....
चेक/डीडी नं..... (छत्तीसगढ़ से बाहर के चेक के लिए 50/- रुपए अतिरिक्त दें. ऐट पार चेक के लिए लागू नहीं)

अथवा

"नेशन अलर्ट" के बैंक खाते (युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, राजनांदगांव : खाता क्रं. 1698050002295)
में अपने नाम से राशि जमा कराएं व हमें सूचित करें।

नाम : ..... पता :.....

शहर : ..... जिला : ..... राज्य : ..... पिन नं. : .....

फोन नं. : ..... मोबाइल फोन : ..... ई-मेल : .....

हमसे संपर्क करें

मोबाइल नंबर
97524-11311
97706-56789

E-mail : nationalertcg@gmail.com
Follow Us : www.facebook.com/nationalert

हमसे जुड़ें और रहें अलर्ट
लाईक कीजिए फेसबुक पर नेशन अलर्ट के
पेज को और अपडेट लीजिए खबरों का...

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया

तरक्की के 13 साल

# छत्तीसगढ़ सरकार विकास लगातार

# स्वस्थ जीवन खुशहाल प्रदेश

## राज्य के सभी परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

## 13 वर्ष की उपलब्धियाँ

- शिशु मृत्यु दर- 76 प्रति हजार से घटकर 43 प्रति हजार
- मातृ मृत्यु दर- 407 प्रति लाख से घटकर 221 प्रति लाख
- सम्पूर्ण टीकाकरण- 56 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत
- संस्थागत प्रसव- 18 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत
- मेडिकल कॉलेज- 02 से बढ़कर 06
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- 114 से बढ़कर 155
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- 512 से बढ़कर 790
- उप स्वास्थ्य केन्द्र- 3818 से बढ़कर 5186
- 108 संजीवनी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस, 104 आरोग्य सेवा, 1099 मुक्तांजलि एम्बुलेंस सेवा।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सभी परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।
- चिरायु योजना के अन्तर्गत 97 लाख से अधिक स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण।
- मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजनान्तर्गत 6307 और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना से 112 बच्चे लाभान्वित
- सिकल सेल पीड़ितों के लिए सिकल सेल संस्थान की स्थापना।
- सरगुजा में 100 सीटर मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ

## आगामी कार्ययोजना

- डीकेएस भवन रायपुर का सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के रुप में उन्नयन।
- बिलासपुर में राज्य कैंसर अस्पताल की स्थापना।
- नेशनल हाईवे स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना।
- टेली मेडिसिन सुविधा का विस्तार।
- चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में वायरोलाजी लेब की स्थापना।
- सभी मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा यूनिट की स्थापना।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor